DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. **Test Booklet Series**

Serial No.

A

TEST BOOKLET

GENERAL STUDIES PAPER - I

TEST - 1

POLITY

Time Allowed: Two Hours **Maximum Marks: 150**

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. There are total **150 questions** in this question booklet.
2. All questions carry **equal marks**.
3. This booklet contains both Hindi and English versions of the question and their responses.
4. **One-third Marks** will be deducted as a penalty for every given wrong answer.
5. You must write your Roll Number in the space provided at the top of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
6. Immediately after the commencement of the examination, you should check on your Question Booklet. Please verify that no pages or questions are missing, duplicated, unprinted, or torn. If you find any defect in this Booklet, get it replaced immediately by a complete Booklet of the same series.
7. In the event that an error arises related to printing or factual accuracy, the English version of the questions will be considered standard among the Hindi and English versions.
8. An answer sheet will be provided to you separately by the Invigilator to mark the answer. You must write your **Name, Roll No., Question Booklet Series** and other particulars in the space provided, falling which your Answer Sheet will not be evaluated.
9. Each question comprises of four responses - (A), (B), (C) and (D). You are to select ONLY ONE correct response and mark it in your Answer Sheet. Your total marks will depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet.
10. In the Answer Sheet, there are four circles - (A), (B), (C) and (D) against each question. To answer the question you are to mark with a Black/Blue ink ballpoint pen ONLY ONE circle of your choice for each question. If you mark more than one circle for one question, the answer will be treated as wrong.
11. The OMR is going to be evaluated by a computer. So, you must take extreme caution while marking in the answer sheet. Since you cannot erase the answers once marked (with a black ballpoint), please take care to mark it carefully.
12. You should not remove or tear off any sheet for the Question Booklet. You're not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. After the examination has concluded, you must hand over your Answer Sheet to the invigilator. Thereafter, you are permitted to take away the Question Booklet with you.
13. Violation of any of the above instructions may result in action being taken against you by the Institute.

1. इस प्रश्न पुस्तिका में कुल **150 प्रश्न** हैं।
2. सभी प्रश्नों के **अंक समान** हैं।
3. इस पुस्तिका में प्रश्न और उनके विकल्प हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं।
4. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड के रूप में **एक तिहाई अंक** काटे जाएंगे।
5. इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर लिखें। प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
6. परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न-पुस्तिका की जांच कर लें कि पुस्तिका में कोई भी पृष्ठ या प्रश्न बिना छपा हुआ या फटा हुआ या उनका दोहराव तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी सीरीज की दूसरी सही पुस्तिका ले लें।
7. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्नों के अंग्रेजी और हिंदी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर को मानक माना जाएगा।
8. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पर्यवेक्षक द्वारा अलग से एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा। निर्धारित स्थान पर आपको अपना **नाम, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज** और अन्य विवरण लिखना होगा, अन्यथा आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा।
9. प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर- (A), (B), (C) और (D) दिए गए हैं। आपको केवल एक सही उत्तर चुनना है और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। आपका कुल प्राप्तांक उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर होगा।
10. उत्तर पुस्तिका में, प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने चार वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं - (A), (B), (C) और (D)। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसंद के केवल एक वृत्त को काली/नीली स्याही वाले बॉल-पॉइंट पेन से चिह्नित करना है। यदि आप एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।
11. ओएमआर का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। इसलिए, आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर अंकित करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि आप एक बार चिह्नित किए गए उत्तरों को (काले बॉलपॉइंट से) बदल नहीं सकते हैं, इसलिए कृपया इसे सावधानीपूर्वक चिह्नित करने का ध्यान रखें।
12. प्रश्न पुस्तिका से कोई भी पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाना मना है। परीक्षा के समापन पर उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंप दें। इसके बाद, आपको प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
13. ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर संस्थान द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

BPSC PRELIMS MOCK TEST–01

1. With reference to the Charter Act 1813, consider the following statements:
   1. It ended the East India Company's trade monopoly in India, except for the tea trade and trade with China.
   2. It consolidated the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the Company.
   3. The revenues of India now came under the control of the British Parliament.

   Which of the above statements is/are correct?

   A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
   C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

2. Consider the following statements regarding Absolute Veto:
   1. A veto can be exercised in Private Bills.
   2. It was exercised for the Office of Profit Bill, 2006.

   Which of the statements given above is/are correct?

   A. Only 1 B. Only 2
   C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

3. **Assertion (A):** The Gram sabha is granted constitutional standing by the 73rd Amendment Act to the constitution.

   Reason (R): Gram Sabha was formally mentioned in the report of the Balwant Rai Mehta committee.

   A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A
   B. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A
   C. Assertion is True but Reason is False
   D. Assertion is False but Reason is True

4. Who said that "the Constituent Assembly alone can frame an indigenous Constitution for the country and truly and fully represent the will of the people"?

   A. Mahatma Gandhi B. Dr. B.R. Ambedkar
   C. Jawaharlal Nehru D. Annie Besant.

1. चार्टर अधिनियम, 1813 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. इसके माध्यम से चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार को छोड़कर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
   2. इसके माध्यम से कंपनी के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को स्थापित किया गया।
   3. भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

   A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
   C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

2. पूर्ण वीटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. निजी विधेयकों में वीटो का प्रयोग किया जा सकता है।
   2. इसका प्रयोग लाभ के पद विधेयक, 2006 के लिए किया गया था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

   A. केवल 1 B. केवल 2
   C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

3. **कथन (A):** संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

   कारण (R): बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का औपचारिक रूप से उल्लेख किया गया था।

   A. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
   B. A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   C. कथन A सही है लेकिन कारण R गलत है।
   D. कथन A गलत है लेकिन कारण R सही है।

4. किसने कहा था कि "संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है"?

   A. महात्मा गांधी B. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
   C. जवाहरलाल नेहरू D. एनी बेसेंट

5. According to the constitution of India which of the following is/are ground for disqualification of membership of the State Legislature:
1. He is an undischarged insolvent.
2. He must not have any interest in government contracts, works or services.
3. He must not have been dismissed from government service for corruption.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. 1, 2, and 3 D. None of the above

5. भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा/से राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता का आधार है/हैं:
1. वह एक अनुन्मोचित दिवालिया हो।
2. उसे सरकारी ठेकों, कार्यों या सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए।
3. उसे भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. 1, 2, 3 D. इनमें से कोई नहीं

6. Consider the following events and arrange them in correct chronological order, from the first to the last activity:
(I) Appointment of the Drafting Committee.
(II) Adopted and enacted the Constitution of India.
(III) The date of commencement of the Constitution of India.
(IV) First meeting of the Constituent Assembly.

Choose the correct options from the codes given below-

A. (IV) (I) (II) (III) B. (I) (II) (IV) (III)
C. (IV) (I) (III) (II) D. (III) (II) (I) (IV)

6. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें पहले से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
(I) प्रारूप समिति की नियुक्ति।
(II) भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया।
(III) भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तिथि।
(IV) संविधान सभा की पहली बैठक।

A. (IV) (I) (II) (III) B. (I) (II) (IV) (III)
C. (IV) (I) (III) (II) D. (III) (II) (I) (IV)

7. The Governor of a state performs which of the following functions?
1. He/She exercises executive, legislative and judicial powers only.
2. He/She has to always act with the aid and advice of the council of ministers.
3. He/She has the power to appoint and remove the members of the state finance commission.

Which of the statements given above are correct?

A. 1 and 2 Only B. 2 and 3 Only
C. 3 Only D. None of the above

7. किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य करता है?
1. वह केवल कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
2. उसे हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होता है।
3. उसके पास राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने की शक्ति है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. Which of the following has been added to the scope of the Right to Life (Article 21) by the Supreme Court?
1. Right to receive minimum wages
2. Right to guaranteed employment for 100 days in a year
3. Right to live with dignity
4. Right to livelihood

Select the correct answer using the codes given below:

A. Only 1 and 3 B. Only 3 and 4
C. Only 1, 2 and 3 D. 1, 2, 3 and 4

8. सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसे जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) के दायरे में जोड़ा है?
1. न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार
2. साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का अधिकार
3. सम्मान से जीने का अधिकार
4. आजीविका का अधिकार

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 3 B. केवल 3 और 4
C. केवल 1, 2 और 3 D. 1, 2, 3 और 4

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

9. In the Government of India Act 1919, the functions of the Provincial Government were divided under the subjects Reserved and Transferred. Which of the following were considered 'Reserved' subjects?

1. Administration of Justice
2. Local Self Government
3. Land Revenue
4. Police

Select the correct answer using the code given below

A. 1, 2, and 3 B. 2, 3, and 4
C. 1, 3, and 4 D. 1, 2, and 4

10. Which among the following participate in the election of the President of India?

1. The nominated members of both the Houses of Parliament.
2. The elected members of the Legislative Assemblies of the States.
3. The nominated members of the State Legislative Assemblies.
4. The elected members of the Legislative Assemblies of the Union Territories.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1, 2 and 3 B. Only 2 and 4
C. Only 1, 2 and 4 D. 1, 2, 3 and 4

11. Consider the following statements regarding the features of the 74th Amendment Act of 1992:

1. The Governor of a specific state may direct that the provisions of the Act be modify as per his discretion.
2. The state legislature may make provisions with respect to the maintenance of accounts by municipalities.
3. The act does not provide for any specific time period for any municipality.

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 Only B. 2 Only
C. 2 and 3 Only D. 1, 2 and 3

9. भारत सरकार अधिनियम, 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे 'आरक्षित' विषय माना जाता था?

1. न्याय का प्रशासन
2. स्थानीय स्वशासन
3. भू-राजस्व
4. पुलिस

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए -

A. 1, 2 और 3 B. 2, 3 और 4
C. 1, 3 और 4 D. 1, 2 और 4

10. निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है?

1. संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य।
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
3. राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य।
4. केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

11. 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी विशिष्ट राज्य के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों को उनके विवेक के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।
2. राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है।
3. यह अधिनियम किसी भी नगर पालिका के लिए किसी विशिष्ट समय अवधि का प्रावधान नहीं करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 2 और 3 D. 1,2 और 3

12. Which of the following best describes the term "Judicial dynamism"?

A. It implies that the role of judges should be scrupulously limited.

B. It requires a Judge, who has been appointed to hear and determine a case, to stand down from that case.

C. It requires NGOs to fight cases of downtrodden sections of society.

D. The assertive role played by the judiciary to force the other two organs of the government, legislature and executive, to discharge their constitutional duties.

12. निम्नलिखित में से कौन "न्यायिक गतिशीलता" शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

A. इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की भूमिका ईमानदारी होनी चाहिए।

B. इसमें एक न्यायाधीश को, जिसे किसी मामले की सुनवाई और निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया है, उस मामले से अलग करना होता है।

C. इसके अंतर्गत समाज के दलित वर्गों के केस को लड़ने के लिए गैर सरकारी संगठन की आवश्यकता होती है।

D. सरकार के अन्य दो अंगों, विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा निभाई गई मुखर भूमिका।

13. Under which Article of the Constitution of India, a Bill which levies tax without the recommendation of the President cannot be introduced in the legislature?

A. Article 117 B. Article 266

C. Article 306 D. Article 307

13. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है?

A. अनुच्छेद 117 B. अनुच्छेद 266

C. अनुच्छेद 306 D. अनुच्छेद 307

14. Consider the following statements with reference to the "PESA Act of 1996":

1. The central government may nominate such Scheduled Tribes which have no representation in the Panchayat at the intermediate level or the Panchayat at the district level.
2. Every village shall have a Gram Sabha consisting of persons whose names are included in the electoral rolls for the Panchayat at the village level.
3. The prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be mandatory for the grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction.

Which of the statements given above are correct?

A. 1 and 2 Only B. 2 and 3 Only

C. 1 and 3 Only D. 1, 2 and 3

14. "पेसा अधिनियम 1996" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
2. प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं।
3. नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत देने हेतु ग्राम सभा अथवा उचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

15. Consider the following statements regarding Speaker of the Assembly:

1. He resigns by writing to Chief Minister.
2. He is the final interpreter of rules of procedure and conduct of business of assembly.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2

C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

15. विधानसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है।
2. वह विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का अंतिम व्याख्याता होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

KGS IAS

16. Match List-I with List-II and select the correct answer with the help of the code given at the bottom of the lists.

List I	List II
a. Part XV of the Constitution	1. Emergency Provisions
b. Part XVI of the Constitution	2. Official Language
c. Part XVII of the Constitution.	3. Special provisions with respect to certain sections.
d. Part XVIII of the Constitution	4. Electoral

A. a-3,b-4,c-1,d-2 B. a-4,b-3,c-2,d-1
C. a-1,b-2,c-3,d-4 D. a-2,b-1,c-4,d-3

16. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

सूची I	सूची II
a. संविधान का भाग XV	1. आपातकालीन प्रावधान
b. संविधान का भाग XVI	2. राजभाषा
c. संविधान का भाग XVII.	3. कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
d. संविधान का भाग XVIII	4. चुनाव

A. a-3,b-4,c-1,d-2 B. a-4,b-3,c-2,d-1
C. a-1,b-2,c-3,d-4 D. a-2,b-1,c-4,d-3

17. Consider the following statements:

1. The judges of a high court are appointed by the Governor.
2. The Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the Parliament.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
2. संविधान उच्च न्यायालय की शक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे संसद के विवेक पर छोड़ता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

18. The Preamble of the Constitution of India aims to ensure that all its citizens

1. Social and Economic Justice
2. Freedom of Thought and Expression
3. Equality of Opportunity
4. Dignity of the individual

Choose the correct answer from the following codes.

A. 1 and 2 only B. 1, 2 and 3 only
C. 2, 3 and 4 only D. 1,2,3 and 4

18. भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने सभी नागरिकों को

1. सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना
2. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
3. अवसर की समानता सुनिश्चित करना
4. व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना

निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 2 और 3
C. केवल 2, 3 और 4 D. 1,2, 3 और 4

19. Consider the following statements regarding "Delimitation Commissions":

1. Commissions have been constituted 5 times so far.
2. Orders of the commission cannot be questioned before any court of law.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

19. "परिसीमन आयोग" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अब तक 5 बार आयोग का गठन किया जा चुका है।
2. आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 D. न तो 1, न ही 2

20. Consider the following statements with reference to Judiciary of India:

1. The President can appoint a judge of the Supreme Court as an acting Chief Justice of India.
2. With the previous consent of the president, the Chief Justice of India can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period.
3. The retired judge who is acting as a judge of the Supreme Court for a temporary period will enjoy all the jurisdiction, powers and privileges of a judge of the Supreme Court.

Which of the statements given above are correct?

A. 1 and 2 Only
B. 2 and 3 Only
C. 1 and 3 Only
D. 1, 2 and 3

21. Consider the following statements, regarding president's veto power:

1. A Constitutional Amendment Bill can only be assented.
2. The President has more Veto power regarding the Ordinary Bill as compared to the Money Bill.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1
B. Only 2
C. Both 1 and 2
D. Neither 1 nor 2

22. In which of the following cases, the Supreme Court held that the Preamble is a part of the Constitution?

A. Union of India vs. Dr. Kohli
B. Banarasi Das vs. State of U.P.
C. Lic Of India Case 1995
D. Berubari Union Case 1960

23. Which of the following organizations/departments is presided by the President of India?

A. Indian Red Cross Society
B. Department of Atomic Energy
C. National Legal Services Authority
D. Defense Research and Development Organization

20. भारत की न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।
2. राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।
3. सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों का लाभ मिलेगा।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

21. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह संविधान संशोधन विधेयक को केवल अनुमोदित कर सकता है।
2. राष्ट्रपति के पास धन विधेयक की तुलना में साधारण विधेयक के संबंध में अधिक वीटो शक्ति होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1, न ही 2

22. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है?

A. भारत संघ बनाम डॉ. कोहली
B. बनारसी दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
C. एलआईसी ऑफ इंडिया मामला 1995
D. बेरुबारी यूनियन केस 1960

23. निम्नलिखित में से किस संगठन/विभाग की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं?

A. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी
B. परमाणु ऊर्जा विभाग
C. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
D. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

24. With reference to the Judiciary of India, Consider the following statements:
1. The term "Contempt of court" has been defined by the Contempt of Court Act of 1971.
2. Article 129 grants the High Court the power to punish for contempt of itself.
3. The purpose of contempt jurisdiction is to uphold the dignity of the judiciary.

Which of the above statements is/are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 3
C. Only 1 and 2 D. All of the above

24. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. "न्यायालय की अवमानना" शब्द को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया है।
2. अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।
3. अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है।

उपर्युक्त कथनों में से किसने सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 3
C. केवल 1 और 2 D. उपर्युक्त सभी

25. Consider the following statements:
1. The Parliament of India can add a particular law to the Ninth Schedule of the Constitution of India.
2. The validity of any law enshrined in the Ninth Schedule cannot be tested by any court and no decision can be taken thereon.

Which of the above statements is/are correct?

A. 1 only B. 2 only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत की संसद भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून जोड़ सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में निहित किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और न ही उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

26. Consider the following statements with reference to "Judicial review":
1. It can be defined as the power of the judiciary to examine the constitutionality of executive orders of both the Central and State governments.
2. The Supreme Court has not declared the power of judicial review as an element of basic structure of the Constitution so far.
3. The Judicial review is needed to uphold the principle of the supremacy of the Constitution.

Which of the above statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 3
C. Only 2 and 3 D. None of the above

26. "न्यायिक समीक्षा" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय ने अब तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का तत्व घोषित नहीं किया है।
3. संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3 D. इनमें से कोई नहीं

27. Consider the following statements:
1. The judge of the Supreme Court can be removed on the ground of proved misbehaviour.
2. The Lok Sabha must sign the motion with at least half of the majority in order to begin the removal of a Supreme Court judge.
3. The speaker/chairman is under obligation to admit the motion of removal of the judge of the Supreme Court.

Which of the statements given above are correct?

A. 1 Only B. 1 and 2 Only
C. 2 and 3 Only D. 1, 2 and 3

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है।
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा को कम से कम आधे बहुमत के साथ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना होगा।
3. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्पीकर/चेयरमैन के अधीन है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

28. Consider the following pairs:

Article	Related provision
1. Article 158	Appointment of the same person as Governor for two or more States
2. Article 153	Governor not holds any other office of profit
3. Article 165	Power of Governor to grant pardons
4. Article 161	Appointment of the Advocate General for the State

Which of the above pairs is/are incorrectly matched?

A. Only 1 B. Only 1 and 4
C. Only 1,3 and 4 D. All of the above

28. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

अनुच्छेद	संबंधित प्रावधान
1. अनुच्छेद 158	दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
2. अनुच्छेद 153	राज्यपाल किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता है
3. अनुच्छेद 165	राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति
4. अनुच्छेद 161	राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति

उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 4
C. केवल 1,3 और 4 D. उपर्युक्त सभी

29. Consider the following statements with reference to the "High court":

1. All the High courts which exist today were set up under the provisions of the Indian High Courts Act, 1861
2. The Writ jurisdiction of the High court kept outside the doctrine of basic structure doctrine.
3. Under Article 220, the President may transfer a Judge from one High Court to another High Court.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 3 B. Only 2 and 3
C. Only 1 D. None

29. "उच्च न्यायालय" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान में मौजूद सभी उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे।
2. उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत से बाहर रखा गया है।
3. अनुच्छेद 220 के तहत, राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 3 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 D. इनमें से कोई नहीं

30. Two statements are given below, in which one is called Assertion (A) and the other is called Reason (R) -

Assertion (A): The elements of 'continuity and change' are embodied in the nature of the Indian political system.

Reason (R): The Indian political system has elements of the following political styles - Modern Style, Traditional Style and Sant Style.

Select the correct answer

A. Both (A) and (R) are correct, but R is the correct Explanation of A
B. Both (A) and (R) are correct, but R is not the correct Explanation of A
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.

30. नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा जाता है -

अभिकथन (A): भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में 'निरंतरता और परिवर्तन' के तत्व समाविष्ट हैं।

कारण (R): भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक शैलियों- आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व हैं।

सही उत्तर का चयन कीजिए

A. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण है
B. (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
C. (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
D. (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

31. Consider the following statements regarding "Ordinance"-

1. It can be promulgated when either of the houses is not in session.
2. The satisfaction of the President is final and beyond judicial review.
3. It ceases to operate on the expiry of three weeks from the reassembly of Parliament.

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 only B. 1 and 2 only
C. 1, 2 and 3 D. None of the above

31. "अध्यादेश" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसे तब प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में न हो।
2. राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है।
3. संसद की पुनः बैठक के तीन सप्ताह की समाप्ति पर इसका संचालन समाप्त हो जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. 1, 2 और 3 D. इनमें से कोई नहीं

32. Consider the following statements:

1. A Panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall serve the entire five years.
2. All the state laws relating to panchayats shall be ended with immediate effect at the commencement of the 73rd Constitutional Amendment Act (1992).
3. All the members of panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people.

Which of the statements given above are correct?

A. Only 3 B. Only 2
C. Only 1 and 3 D. None of the above

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी पंचायत की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विघटन पर गठित पंचायत पूरे पांच वर्ष तक कार्य करेगी।
2. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के प्रारंभ होते ही पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेंगे।
3. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 3 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

33. By definition, constitutional government means -

A. Government by legislature
B. Popular government
C. Multi-party government
D. Limited government.

33. परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ है -

A. विधायी सरकार
B. लोकप्रिय सरकार
C. बहुदलीय सरकार
D. सीमित सरकार

34. Consider the following statements with reference to the "Gram Nyayalayas":

1. These shall be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act, 1872
2. They are mobile courts and shall exercise the powers of both Criminal and Civil Courts.
3. The presiding officer shall be appointed by the State Government in consultation with the High Court.

Which of the above statements given above is/are correct?

A. Only 2 and 3 B. Only 3
C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

34. "ग्राम न्यायालय" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में दिए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य होंगे।
2. ये गतिशील न्यायालय होते हैं तथा आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
3. पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जायेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3 B. केवल 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

35. Consider the following statements:

1. The advice tendered by the Supreme court on any dispute arising out of any pre-constitution treaty is binding on the President.
2. If any question of law or fact of public importance has arisen the Supreme court may refuse to tender its opinion to the president.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी संविधान-पूर्व संधि से उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
2. यदि कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य का कोई प्रश्न उठता है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने से इनकार कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

36. Consider the following statements regarding the Union and its jurisdiction.

1. India is made up of 28 states and 8 union territories.
2. India is a sovereign, secular, democratic republic with a parliamentary form of government.

Which of the above statements is/are true?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

36. संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है।
2. भारत संसदीय शासन प्रणाली वाला एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

37. In which of the following matters, the powers and status of the Rajya Sabha are equal to that of the Lok Sabha:

1. Election and impeachment of the president.
2. Approval of ordinances issued by the President.
3. Vote on the demands for grants

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 2 and 3 B. Only 1 and 2
C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

37. निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सभा की शक्तियाँ और स्थिति लोकसभा के बराबर है:

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग
2. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूरी
3. अनुदान मांगों पर मतदान

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 2 और 3 B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

38. A parliamentary form of government is one in which-

A. All political parties in the parliament are represented in the government.
B. Government is accountable to Parliament and can be removed by it.
C. Government is elected by the people and can be removed by them.
D. The Government is elected by the Parliament but cannot be removed before the expiry of the prescribed period.

38. सरकार का संसदीय स्वरूप वह है जिसमें-

A. संसद में सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है।
B. सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे इसके द्वारा हटाया भी जा सकता है।
C. सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और उसे इनके द्वारा हटाया भी जा सकता है।
D. सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है लेकिन निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उसे हटाया नहीं जा सकता।

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

39. As a federal court the Supreme Court has exclusive original jurisdiction in a few cases. This jurisdiction of the Supreme Court does *not* extend to which of the following cases?

1. A dispute arising out of any pre-Constitution treaty agreement.
2. Adjustment of certain expenses and pensions between the Centre and the states.
3. Any dispute between the Centre and any state or states on one side and one or more other states on the other side.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3 D. None

40. Original Jurisdiction means the power of a high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal. Which of the following is/are included under original jurisdiction of the High Court?

1. Enforcement of fundamental rights of citizens.
2. Disputes relating to the election of members of Parliament and state legislatures.
3. Cases ordered to be transferred from a subordinate court involving the interpretation of the Constitution to its own file.

Select the correct answer using the code given below-

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. 1, 2 and 3 D. None

41. Correctly match the following Union Territories with the year of their formation -

Union Territory	Year
A. Lakshadweep	(i) 1961
B. Daman and Diu	(ii) 1966
C. Chandigarh	(iii) 1962
D. Dadra and Nagar Haveli	(iv) 1956

A. A-(i), B-(ii), C-(iii), D-(iv)
B. A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(i)
C. A-(iv), B-(ii), C-(iii), D-(i)
D. A-(i), B-(iii), C- (ii), D-(iv)

39. एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में विशेष मूल क्षेत्राधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले तक विस्तारित नहीं है?

1. संविधान-पूर्व किसी संधि समझौते से उत्पन्न विवाद।
2. केंद्र और राज्यों के बीच नियत व्यय और पेंशन का समायोजन।
3. केंद्र और किसी राज्य के बीच कोई विवाद या एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. इनमें से कोई नहीं

40. मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की अपील के बजाय पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा/से उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है/हैं?

1. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
2. संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद।
3. संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देना।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. 1, 2 और 3 D. इनमें से कोई नहीं

41. निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके गठन के वर्ष से सुमेलित कीजिए -

केंद्र शासित प्रदेश	वर्ष
A. लक्षद्वीप	(i) 1961
B. दमन और दीव	(ii) 1966
C. चंडीगढ़	(iii) 1962
D. दादरा और नगर हवेली	(iv) 1956

A. A-(i), B-(ii), C-(iii), D-(iv)
B. A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(i)
C. A-(iv), B-(ii), C-(iii), D-(i)
D. A-(i), B-(iii), C-(ii), D-(iv)

42. The provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act can be grouped into two categories: compulsory and voluntary. Which of the following are part of voluntary provisions?
1. Establishment of a State Election Commission.
2. Reservation of one-third seats for women in panchayats at all the three levels.
3. Determining the manner of election of the chairperson of the village panchayat.
4. Making the grants-in-aid to the panchayats from the consolidated fund of the state.

Select the correct answer using the code given below:

A. 1 and 2 Only B. 2 and 3 Only
C. 3 and 4 Only D. 1 and 4 Only

43. Consider the following statements:
1. Presidential Impeachment charges should be passed by two-third of members that framed the charges.
2. An impeachment is a Quasi-Judicial procedure in the Parliament.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

44. Consider the following pairs:

List I	List II
1. Respite	Awarding a lesser sentence in place of one originally awarded
2. Remission	Substitution of form of punishment
3. Reprieve	Reducing the period of sentence without changing its character

Which of the above pairs given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. Only 2 and 3 D. All of the above

45. Which of the following Supreme Court cases are related to disputes/conflicts between fundamental Rights and Directive Principles of State Policy?
1. Champakam Dorairajan Case, 1951
2. K.S.Puttaswamy Case, 2018
3. Kesavananda Bharati case, 1973
4. Golaknath case, 1967

Select the correct answer using the code given below.

A. 1, 2 and 3 B. 3 and 4 Only
C. 2, 3 and 4 Only D. 1, 3 and 4 Only

42. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: अनिवार्य और स्वैच्छिक। निम्नलिखित में से कौन स्वैच्छिक प्रावधानों का हिस्सा हैं?
1. राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।
2. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना।
3. ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना।
4. राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4 D. केवल 1 और 4

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति पर महाभियोग के आरोप को आरोप तय करने वाले दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
2. महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

44. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

सूची I	सूची II
1. विराम	मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर सजा को कम करना
2. परिहार	सजा के स्वरूप का प्रतिस्थापन
3. प्रविलंबन	दंड का स्वरूप बदले बिना सजा की अवधि कम करना

उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. उपर्युक्त सभी

45. निम्नलिखित में से कौन-सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच विवाद/संघर्ष से संबंधित है?
1. चंपकम दोराइराजन वाद, 1951
2. के.एस.पुट्टास्वामी वाद, 2018
3. केशवानंद भारती वाद, 1973
4. गोलकनाथ वाद, 1967

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. 1, 2 और 3 B. केवल 3 और 4
C. केवल 2, 3 और 4 D. केवल 1, 3 और 4

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

46. Consider the following statements regarding the Fundamental Duties of an Indian citizen:
1. They serve as a warning against anti-national and antisocial activities.
2. They help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.
3. They serve as a source of inspiration for the citizens.
4. They are enforceable by law.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1,2 and 3 D. 1, 2, 3 and 4

47. Consider the following statements with reference to the States Reorganisation Commission, 1953:
1. Justices Fazal Ali, KM Panikkar and Hridaynath Kunzru were its members.
2. The Commission supported the partition of Bombay and Punjab.
3. As per the States Reorganisation Act, 1956, 14 States and 6 Union Territories were created.

Which of the above statements is/are correct?

A. 1, 2 and 3 only B. 1 and 2 only
C. 1 only D. 1 and 3 only

48. Which of the following is/are among the Fundamental Duties of citizens laid down in the Indian Constitution?
1. To prohibit the consumption of intoxicated drinks.
2. To value and preserve the rich heritage of our composite culture.
3. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
4. To safeguard public property and to abjure violence.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1, 2 and 3 B. Only 1, 2 and 4
C. Only 2, 3 and 4 D. 1, 2, 3, 4

49. Consider the following statements, with reference to Attorney General of India:
1. He/she has the right to audience in all courts in India.
2. His/her fees for private legal practice are separate from the salary received for holding the office.
3. He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of Parliament.

Which of the above statements is/are correct?

A. Only 1 and 3 B. Only 3
C. 1, 2, and 3 D. Only 2

46. भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?
1. ये राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
2. ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं।
3. ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
4. ये कानून द्वारा प्रवर्तनीय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1,2 और 3 D. 1,2,3 और 4

47. राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जस्टिस फजल अली, केएम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे।
2. इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया।
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 D. केवल 1 और 3

48. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में से है/हैं?
1. नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना।
2. हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
4. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 2 और 4
C. केवल 2, 3 और 4 D. 1, 2, 3, 4

49. भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उसे भारत की सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है।
2. निजी कानूनी प्रैक्टिस के लिए उसकी फीस महान्यायवादी के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन से अलग होता/होती है।
3. संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ उसे भी प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 3
C. 1,2,3 D. केवल 2

50. Under Article 19 (2), 'reasonable restrictions' on the exercise of freedom of speech and expression may be justified in which of the following circumstances?

1. State Security
2. Defamation
3. Sedition
4. Public Order.

Which of the statements given above is/ are correct?

A. 1, 2 only B. 2, 3 only
C. 1, 2 and 4 only D. 1, 2, 3 and 4

50. अनुच्छेद 19(2) के तहत, 'वाक् और अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित हो सकते हैं?

1. राज्य की सुरक्षा
2. मानहानि
3. राजद्रोह
4. सार्वजनिक व्यवस्था

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

A. केवल 1,2 B. केवल 2,3
C. केवल 1, 2 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

51. While the proclamation of national emergency is in operation, which of the following authorities can modify the constitutional distribution of revenues between the Centre and the states?

A. Parliament B. Governor
C. President D. Finance commission

51. निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू है?

A. संसद B. राज्यपाल
C. राष्ट्रपति D. वित्त आयोग

52. Consider the following statements with reference to the "Vice-President of India":

1. He/she is elected by an electoral college consisting of the members of both the Houses of Parliament and the Legislative Assemblies of States.
2. He/she can be removed only through impeachment proceedings similar to that of the President of India.

Which of the statements given above is/are incorrect?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

52. "भारत के उपराष्ट्रपति" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं।
2. उसे भारत के राष्ट्रपति के समान महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

53. Which one of the following is correct?

A. The Nehru Report (1928) supported the inclusion of Fundamental Rights in the Indian Constitution.
B. The Government of India Act 1935 gave shelter to Fundamental Rights.
C. The August Resolution, 1940 had incorporated Fundamental Rights.
D. The Cripps Mission, 1942 enshrined fundamental rights.

53. निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. नेहरू रिपोर्ट (1928) ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया।
B. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मौलिक अधिकारों को आश्रय दिया।
C. अगस्त प्रस्ताव, 1940 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था।
D. क्रिप्स मिशन, 1942 ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया।

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

54. Which of the following statements is **NOT** correct?

A. A person to be elected to the legislative council must be an elector for an assembly constituency in the concerned state.

B. A person to be qualified for the Governor's nomination must be a resident in the concerned state.

C. A person to be elected to the legislative assembly must be an elector for an assembly constituency in the concerned state.

D. A member of scheduled castes or scheduled tribes cannot contest a seat not reserved for them.

54. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

A. विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।

B. राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए।

C. विधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।

D. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उनके लिए आरक्षित नहीं है।

55. Consider the following pairs:

Article	Related provision
1. Article 42	Right to work, to education and to public assistance.
2. Article 41	Humane conditions of work and for maternity relief.
3. Article 43(A)	Promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas
4. Article 43	Secure the participation of workers in the management of undertakings

Which of the above pairs is/are incorrectly matched?

A. Only 1 B. Only 1 and 2

C. Only 1, 2 and 3 D. 1, 2, 3 and 4

55. निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए:

	अनुच्छेद	संबंधित प्रावधान
1.	अनुच्छेद 42	काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
2.	अनुच्छेद 41	काम की मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत
3.	अनुच्छेद 43(A)	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
4.	अनुच्छेद 43	उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना

उपर्युक्त में से कौन-सा/से जोड़ा सही सुमेलित नहीं है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2

C. केवल 1, 2 और 3 D. 1, 2, 3 और 4

56. State Legislative Council share equal power with the State Legislative Assembly. In this regard consider the following statements:

1. A Money Bill can be introduced only in the assembly.
2. Legislative council can vote on the demands for grants.
3. Enlargement of the jurisdiction of the state public service commission.

Which of the following statements is/are correct?

A. Only 3 B. Only 1 and 2

C. Only 1 D. All of the Above

56. राज्य विधान परिषद राज्य विधान सभा के साथ समान शक्ति साझा करती है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. विधान परिषद अनुदान मांगों पर मतदान कर सकती है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 3 B. केवल 1 और 2

C. केवल D. उपयुक्त सभी

57. Consider the following statements with reference to "Directive Principles of States Policies":

1. The Constitution classifies it into three broad categories - Socialistic, Gandhian, and Liberal.
2. Its objective is to establish political democracy in the country.

Which of the statements given above is/are incorrect?

A. 1 Only B. 2 Only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

58. With reference to India, consider the following statements:

1. When a prisoner presents sufficient grounds, Parole cannot be denied to such a prisoner as it becomes a matter of his right.
2. State governments have their own rules for releasing a prisoners on parole.

Which of the above statements is/are correct?

A. 1 only B. 2 only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

59. "There is equal pay for equal work for both men and women" is given under which article of indian constitution?

A. Article 39 (a) B. Article 39 (b)
C. Article 39 (c) D. Article 39 (d)

60. Which of the following statements is/are correct about the Directive Principles of State Policy?

1. It serves as guidelines for the legislature only.
2. They are mentioned in Part VI of the Constitution.

Select the correct answer using the codes given below.

A. 1 Only B. 2 Only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

61. Consider the following statements:

1. Zero Hour is a formal device available to raise matters without any prior notice.
2. Short notice questions are answered in writing.

Which of the statement given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

57. "राज्यों की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान इसे तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है - समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी।
2. इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

58. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, तो ऐसे कैदी को पैरोल से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।
2. किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

59. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत "पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन" का प्रावधान दिया गया है?

A. अनुच्छेद 39 (a) B. अनुच्छेद 39 (b)
C. अनुच्छेद 39 (c) D. अनुच्छेद 39 (d)

60. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह केवल विधायिका के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है।
2. इनका उल्लेख संविधान के भाग VI में किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

61. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शून्यकाल एक औपचारिक उपकरण है जो बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाने के लिए उपलब्ध है।
2. अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

62. Choose the correct chronology of the following decisions relating to Fundamental Rights:

1. Golaknath v. State of Punjab
2. Kesavananda Bharati v. State of Kerala
3. Minerva Mills v. Union of India
4. A.K. Gopalan v. State of Madras

Select the correct answer

A. 1-2-3-4 B. 2-1-3-4
C. 4-1-2-3 D. 3-1-2-4

63. Consider the following statements:

1. The origin of this committee can be traced to the standing financial committee set up in 1921.
2. In the post-independence era this committee was constituted on the recommendation of John Mathai.
3. All the thirty members of this committee are from Lok Sabha only.

Which of the following committees is mentioned in the above statements?

A. Public account committee
B. Estimate committee
C. Ethics committee
D. Committee on Public Undertakings

64. Consider the following statements regarding the duration of legislative council in a State:

1. It is a permanent body and is not subject to dissolution.
2. One-third of its members retire on the expiration of every three years.
3. The retiring members are eligible for re-election but not for re-nomination.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. Only 3 D. Only 2 and 3

65. The Constitution grants the right against exploitation to which of the following?

1. Children
2. Women
3. Tribes

Choose the correct options using the codes given below-

A. 1 and 2 Only B. 1 and 3 Only
C. 1, 2 and 3 Only D. 2, 3 and 4 Only

62. मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए:

1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
3. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
4. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

सही उत्तर का चयन कीजिए

A. 1-2-3-4 B. 2-1-3-4
C. 4-1-2-3 D. 3-1-2-4

63. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है।
2. स्वतंत्रता के बाद इस समिति का गठन जॉन मथाई की अनुशंसा पर किया गया था।
3. इस समिति के सभी तीस सदस्य लोकसभा से ही हैं।

उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस समिति का उल्लेख किया गया है?

A. लोक लेखा समिति
B. प्राक्कलन समिति
C. आचार समिति
D. सार्वजनिक उपक्रम समिति

64. किसी राज्य में विधान परिषद की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है।
2. इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक तीन वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
3. सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुन: चुनाव के लिए पात्र होते हैं लेकिन पुन: नामांकन के लिए नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 3 D. केवल 2 और 3

65. संविधान निम्नलिखित में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है?

1. बच्चे
2. महिला
3. जनजाति

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए-

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3
C. केवल 1, 2 और 3 D. केवल 2, 3 और 4

66. Consider the following statements regarding the Fundamental Duties of an Indian Constitution.

1. The Fundamental Duties are confined to citizens only.
2. Some of them are moral duties while others are civic duties.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

66. भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित हैं।
2. उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

67. **Assertion (A):** Article 30 of the Indian Constitution does not define the term "minority"

Reason (R): The Constitution recognises only linguistic and religious minorities

Choose the correct answer from the codes given below:

A. Both (A) and (R) are true and R is the correct explanation of A.
B. Both (A) and (R) are true and R is not the correct explanation of A.
C. (A) is true, but (R) is false.
D. (A) is false, but (R) is true.

67. **अभिकथन (A)-** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं करता है।

कारण (R)- संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
B. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
C. (A) सत्य है, लेकिन (R) गलत है।
D. (A) गलत है, लेकिन (R) सत्य है।

68. Consider the following statements regarding the Comptroller and Auditor General of India (CAG):

1. The office of the CAG is provided by Article 148 of the Indian Constitution.
2. The CAG is the guardian of the public purse only at the Centre and not at the state.
3. The CAG was called as the most important officer under the Constitution of India by Dr. B.R. Ambedkar.

Which of the statements given above are correct?

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

68. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CAG का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा प्रदान किया गया है।
2. CAG केवल केंद्र में जनता के धन का संरक्षक है, राज्य में नहीं।
3. CAG को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

69. Prior recommendation of the President is required before the introduction of a Bill in which of the following cases?

1. Bill involving expenditure from the Consolidated Fund of India.
2. Bill for the alteration of boundaries of states or creation of a new state.
3. Bill involving amendment of the Constitution.
4. Money Bills.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 3 B. Only 2 and 4
C. Only 1, 2 and 4 D. 1, 2, 3 and 4

69. निम्नलिखित में से किस मामले में किसी विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है?

1. भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक
2. राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नये राज्य के गठन हेतु विधेयक
3. संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक
4. धन विधेयक

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 3 B. वल 2 और 4
C. केवल 1, 2 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

70. Which of the following constitutional amendments is/are related to fundamental duties?
1. Forty-second Amendment
2. Forty-fourth Amendment
3. Forty-eighth Amendment
4. Eighty-sixth Amendment

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 4 B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3 D. Only 2 and 4

71. Consider the following statements regarding the immunities enjoyed by the President of India and the Governor of States:
1. No criminal proceedings shall be instituted or continued against the President or the Governor in any court during his term of office.
2. No process for the arrest and imprisonment of the President or or Governor shall be issued from any court during his term of office.
3. No civil proceedings against the President or the Governor shall be instituted during his term of office in any court.

Which of the above statements are correct?

A. 1 and 2 Only B. 2 and 3 Only
C. 1 and 3 Only D. 1, 2 and 3

72. Which one of the following is NOT a fundamental duty?

A. To protect and promote the natural environment
B. To honor the National Anthem
C. To protect monuments and places of national importance
D. To protect public property

73. If for any reason the Vice President discharges the functions of the President in the absence of the President of India, then which statement(s) is/are correct regarding his term?
1. During this period the Vice President will remain the Chairman of the Rajya Sabha.
2. The Vice President will receive the President's salary for this period.
3. If the Vice President resigns during this period, the Chief Justice of India will discharge the office of President.

Choose the correct option given below-

A. 1, 2 and 3 B. 1 and 2 only
C. 2 and 3 only D. 1 only

70. निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है/हैं?
1. बयालीसवाँ संशोधन
2. चवालीसवाँ संशोधन
3. अड़तालीसवां संशोधन
4. छियासीवां संशोधन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 4 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. केवल 2 और 4

71. भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को प्राप्त छूट के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
2. राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी और कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी।
3. राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई नागरिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

72. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?

A. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना
B. राष्ट्रगान का सम्मान करना
C. राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना
D. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना

73. यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उसके कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है/हैं?
1. इस दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे।
2. उपराष्ट्रपति को इस अवधि के लिए राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा।
3. यदि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए-

A. 1, 2 और 3 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. केवल 1

74. Who of the among can be appointed as a judge of Supreme Court?

A. Any resident of India residing in India for seven years
B. Citizen of India who have been a judge of High Court for five years
C. Citizen of India who have been advocate of High Court for five years
D. Citizen of India who have been a judge of district court for seven years.

74. इनमें से किसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है?

A. भारत का कोई भी नागरिक जो सात वर्ष से भारत में रह रहा हो।
B. भारत का नागरिक जो पांच वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
C. भारत का नागरिक जो पांच वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो।
D. भारत का नागरिक जो सात वर्षों तक जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।

75. Which of the following are among the salient features of the Family Courts Act, 1984?

1. It makes it obligatory on the State Governments to set up a Family Court in every city or town with a population exceeding one million.
2. It exclusively provides within the jurisdiction of the Family Courts the matters relating to matrimonial relief.
3. It provides for only one right of appeal which shall lie to the High Court.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 2
B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3
D. 1, 2 and 3

75. निम्नलिखित में से कौन-सी पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की मुख्य विशेषताएं हैं?

1. यह राज्य सरकारों के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
2. यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक राहत से संबंधित मामलों का प्रावधान करता है।
3. यह अपील के लिए केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

76. Consider the statements with reference to the "term of Vice-president of India":

1. The term is five years from the date which he enters upon his office.
2. He/she is eligible for re-election for an unlimited number of terms.
3. He/she can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the Chairman of Rajya Sabha.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 2 and 3
B. Only 1 and 2
C. Only 3
D. None of the above

76. "भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल" के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए:

1. उसका कार्यकाल उसके पदग्रहण की तिथि से पांच वर्ष का होता है।
2. वह असीमित अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है।
3. वह किसी भी समय राज्यसभा के सभापति को त्याग पत्र भेजकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3
B. केवल 1 और 2
C. केवल 3
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

77. Consider the following statements with reference to the "Supreme court of India":

1. Part VI of the Constitution deals with the organisation, independence, jurisdiction, powers, procedures of the Supreme Court.
2. The Number of Judges of the Supreme Court can be increased or decreased by the President.
3. The consultation with the chief justice is obligatory in the case of appointment of a judge other than the Chief justice.

Which of the above statements are incorrect?

A. 1 and 2 Only
B. 2 and 3 Only
C. 3 Only
D. None of the above

77. "भारत के सर्वोच्च न्यायालय" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का भाग VI सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित है।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
3. मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नहीं हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 3
D. इनमें से कोई भी नहीं

78. Who among the following presides over the proceedings of the Rajya Sabha when the offices of both the Speaker and the Deputy Speaker fall vacant?

A. The senior most member of the Rajya Sabha.
B. The person selected by the members of the House from among themselves.
C. Any member of the Rajya Sabha appointed by the President of India.
D. The Union Minister of Parliamentary Affairs.

78. निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं?

A. राज्य सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य।
B. वह व्यक्ति जिसे सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है।
C. भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का कोई भी सदस्य।
D. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री।

79. According to Article 300 of the Constitution of India, the legal name of the Government of India is-

A. The Union Government
B. The Union of India
C. Republic of India
D. Government of India

79. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत सरकार का विधिक नाम है-

A. संघ सरकार
B. राज्यों का संघ
C. भारत गणराज्य
D. भारत सरकार

80. Which of the following writs can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person?

A. Habeas corpus
B. Quo-Warranto
C. Prohibition
D. Certiorari

80. निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि वह पीड़ित व्यक्ति ही हो?

A. बन्दी प्रत्यक्षीकरण
B. अधिकार पृच्छा
C. प्रतिषेध
D. उत्प्रेषण

81. Which of the following taxes levied and collected and retained by the States?

1. Taxes on agricultural income
2. Duties of excise on alcoholic liquors for human consumption
3. Stamp duties on bills of exchange
4. Taxes on the sale or purchase of goods

Select the correct answer using the code below:

A. 1 and 2 only B. 2 and 3 only
C. 3 and 4 only D. 1 and 4 only

82. According to the Indian Constitution, it is the duty of the President of India to table which of the following in the Parliament?

1. Recommendations of the Union Finance Commission
2. Report of the Public Accounts Committee
3. Report of the Comptroller and Auditor General
4. Report of the National Commission for Scheduled Castes

Select the correct options using the codes given below:

A. 1 only B. 2 and 4 only
C. 1, 3 and 4 only D. 1, 2, 3 and 4

83. Consider the following statements with reference to the "73rd Constitutional Amendment Act":

1. This act has added a new (Part-XI) to the Constitution of India.
2. The act has added a new Eleventh Schedule to the Constitution.
3. The act has brought the Panchayati raj institutions under the purview of the justiciable part of the Constitution.

Which of the above statements are true?

A. 1 and 2 Only B. 2 and 3 Only
C. 3 and 4 Only D. 1, 2 and 3 Only

84. If a Bill is returned by the President for reconsideration to Parliament/state legislature which is passed again by the Parliament/state legislature, with or without amendments, the President:

A. Has to give his assent to the Bill.
B. Is not bound to give his assent.
C. Can withhold his assent only up to two months.
D. None of the above.

81. निम्नलिखित में से कौन-सा कर राज्यों द्वारा लगाया, वसूला और बरकरार रखा जाता है?

1. कृषि आय पर कर
2. मानव उपभोग के लिए अल्कोहलिक शराब पर उत्पाद शुल्क
3. विनिमय बिलों पर स्टाम्प शुल्क
4. माल की बिक्री या खरीद पर कर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4 D. केवल 1 और 4

82. भारतीय संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे संसद में प्रस्तुत करना भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है?

1. केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें
2. लोक लेखा समिति की रिपोर्ट
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट

निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए:

A. केवल 1 B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 3 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

83. "73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग-XI जोड़ा है।
2. इस अधिनियम ने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी है।
3. इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायसंगत भाग के दायरे में ला दिया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 और 4 D. केवल 1, 2 और 3

84. यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद/राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, जिसे संसद/राज्य विधायिका द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति:

A. विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है
B. अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है
C. अपनी सहमति केवल दो महीने तक के लिए रोक सकता है
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

85. Which of the following statements is NOT correct regarding a no-confidence motion?

A. The first ever no-confidence motion on the floor of the Lok Sabha was against Jawaharlal Nehru.

B. Indira Gandhi faced a maximum number of no-confidence motions.

C. The member who wants to move a no-confidence motion has to inform the Lok Sabha Speaker in writing.

D. No-confidence motion can be placed only in the Lok Sabha.

86. Consider the following statements:

1. The total amount of taxes on professions, trades, callings and employments imposed by the state legislature should not exceed ₹25,000 per annum.
2. A state legislature can impose a tax on the consumption electricity even if electricity is consumed by the centre.

Which of the above statements given above is/are correct?

A. Only 1　　B. Only 2

C. Both 1 and 2　　D. Neither 1 nor 2

87. With reference to the strength of State Legislature, consider the following statements:

1. The strength of a legislative assembly depends on the population size of the State.
2. The maximum strength of the legislative council is fixed at one-third of the total strength of the assembly.
3. The actual strength of a legislative council is fixed by the legislature of the concerned state.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 and 2　　B. Only 2

C. Only 3　　D. Only 1 and 3

88. Who among the following is present in the meetings of the Public Accounts Committee of Parliament?

A. Attorney General of India

B. Solicitor General of India

C. Comptroller and Auditor General of India

D. None of the above

85. अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?

A. लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरु के विरुद्ध लाया गया था।

B. इंदिरा गांधी को सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा।

C. जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित करना होता है।

D. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।

86. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्य विधायिका द्वारा व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर लगाए गए करों की कुल राशि ₹25,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. एक राज्य विधायिका उपभोग बिजली पर कर लगा सकती है, भले ही बिजली केंद्र द्वारा उपभोग की जाती हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1　　B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों　　D. न तो 1 और न ही 2

87. राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है।
2. किसी विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई निर्धारित है।
3. किसी विधान परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा तय की जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2　　B. केवल 2

C. केवल 3　　D. केवल 1 और 3

88. निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है?

A. भारत के महान्यायवादी

B. भारत के सॉलिसिटर जनरल

C. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

89. Consider the following statements regarding "Governor":

1. No Governor can be removed from office till completion of his term.
2. No Governor can continue in office beyond five years.
3. The Prime Minister can transfer the appointed Governor from one state to another.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1
B. Only 1 and 2
C. Only 3
D. None of the above

89. "राज्यपाल" के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने तक पद से हटाया नहीं जा सकता।
2. कोई भी राज्यपाल पांच वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता।
3. प्रधानमंत्री किसी नियुक्त राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 3
D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

90. Who comes above the Chief Justice of India in the table of precedence of the Government of India?

A. Attorney General of India
B. Former President
C. Chief of Staff
D. Speaker of the Lok Sabha

90. भारत सरकार के पदानुक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर कौन आता है?

A. भारत के महान्यायवादी
B. पूर्व राष्ट्रपति
C. चीफ ऑफ स्टाफ
D. लोकसभा अध्यक्ष

91. Which of the following 'Offices' are provided by the Indian Constitution itself?

1. Attorney General for India
2. Solicitor General of India
3. Comptroller and Auditor General of India

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 and 2
B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3
D. 1, 2 and 3

91. निम्नलिखित में से कौन से 'पद' का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किया गया है?

1. भारत के महान्यायवादी
2. भारत के सॉलिसिटर जनरल
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

92. Which of the following group of States/UTs has only one seat in the Lok Sabha?

A. Goa, Meghalaya, Nagaland
B. Manipur, Dadra and Nagar Haveli, Puducherry
C. Arunachal Pradesh, Sikkim, Lakshadweep
D. Chandigarh, Sikkim, Mizoram

92. निम्नलिखित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के समूहों में से किस समूह में लोकसभा में केवल एक सीट है?

A. गोवा, मेघालय, नागालैंड
B. मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी
C. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप
D. चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

93. Consider the following statements:

1. While a proclamation of National emergency is in operation, the President acquires the power to legislate with respect to matters in the State List.
2. The laws formulated during the National emergency will become inoperative on the expiration of six months after the emergency has ceased to operate.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है, तो राष्ट्रपति को राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने की समाप्ति पर निष्क्रिय हो जाएंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

94. In the questions given below, there are two statements marked as Assertion and Reason (R).

Assertion (A): The Comptroller and Auditor General of India (CAG) holds his office till the pleasure of the President.

Reason (R): The Comptroller and Auditor General of India (CAG) is appointed by the President of India.

Choose the correct option:

A. Both(A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
B. Both(A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A).
C. (A) is correct but (R) is incorrect
D. (A) is incorrect but (R) is correct.

94. नीचे दिए गए प्रश्न में, दो कथन अभिकथन और कारण (R) के रूप में दिए गए हैं।

अभिकथन (A) : भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है।

कारण (R): भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

सही विकल्प का चयन कीजिए-

A. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
B. (A) और (R) दोनों सही हैं और (R) (A) की सही व्याख्या नहीं है।
C. (A) सही है लेकिन (R) गलत है।
D. (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

95. Consider the following statements related to Cabinet Committees -

1. Cabinet committees are not mentioned in the Constitution.
2. Cabinet committees are constituted by the Prime Minister keeping in mind the need of the hour and the situation.
3. If the Prime Minister is a member of the committee, it is not necessary that he be the Chairman of the committee.
4. The Prime Minister is the Chairman of the Parliamentary Affairs Committee.

Which of the following options is correct?

A. 1, 2 and 3 only B. 2, 3 and 4 only
C. 1, 2, 3, 4 D. 1 and 2 only

95. मंत्रिमंडलीय समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है।
2. प्रधानमंत्री द्वारा समय की मांग और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है।
3. यदि प्रधानमंत्री इस समिति के सदस्य हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वो समिति के अध्यक्ष हों।
4. प्रधानमंत्री संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष होते हैं।

निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2, 3 और 4
C. 1, 2, 3 और 4 D. केवल 1 और 2

96. Which committee/commission recommended that "A permanent Inter-State Council called the Intergovernmental Council should be set up under Article 263"?

A. Rajamannar Committee

B. Sarkaria Commission

C. Punchhi Commission

D. JVP committee

97. Consider the following statements:

1. All money bills are financial bills, but not all financial bills are money bills.
2. Joint sitting is applicable to ordinary bills or money bills only and not to Constitutional amendment bills.
3. If the bill has lapsed due to the dissolution of the Lok Sabha, no joint sitting can be summoned.

Which of the statements given above is/are incorrect?

A. Only 2

B. Only 1

C. Only 2 and 3

D. All of the above

98. If the Deputy Speaker is presiding over the Lok Sabha, he has the right to -

A. Participate in the deliberations of the Lok Sabha.

B. As a member, vote on any proposal before the House.

C. Vote in case of equality of votes but not in the first instance.

D. In the absence of the Speaker, he does not have the right to convene a joint meeting of the Parliament.

99. Consider the following statements regarding Individual Privileges for the members of the state legislature.

1. They are exempted from jury service when the state legislature is in session.
2. They cannot be arrested in civil cases during the session of the state legislature.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1

B. Only 2

C. Both 1 and 2

D. Neither 1 nor 2

96. किस समिति/आयोग ने सिफारिश की कि "अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है, स्थापित की जानी चाहिए"?

A. राजमन्नार समिति

B. सरकारिया आयोग

C. पुंछी आयोग

D. जेवीपी समिति

97. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
2. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों या धन विधेयकों पर लागू होती है, संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर नहीं।
3. यदि लोकसभा भंग होने के कारण विधेयक व्यपगत हो जाता है तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 2

B. केवल 1

C. केवल 2 और 3

D. उपरोक्त सभी

98. यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो, तो उसे अधिकार है-

A. लोकसभा के बहसों में भाग लेने का

B. सदस्य के रूप में सदन के समक्ष रखे गए किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का

C. वोट की बराबरी की स्थिति में मतदान करने का (लेकिन पहली बार में नहीं)

D. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसे संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है

99. राज्य विधायिका के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जब राज्य विधायिका का सत्र चल रहा हो तो उन्हें जूरी सर्विस से छूट दी जाती है।
2. राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

100. Consider the following statements-

1. The largest political party in the opposition in the first Lok Sabha was the Swatantra Party.
2. "Leader of Opposition" in the Lok Sabha was first recognized in 1969.
3. If a party does not have a minimum of 75 members in the Lok Sabha, then its leader cannot be recognized as the Leader of the Opposition.

Which of the above statements is/are correct?

A. 1 and 3 only B. 2 only
C. 2 and 3 only D. 1, 2 and 3

101. Consider the following statements:

1. The Borrowing limit of the central government is fixed by the President of India.
2. States can borrow from outside India but with the prior approval of the President of India.
3. Recently, Parliament has enacted a law to fix the borrowing limit of the centre.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2 and 3
C. Only 3 D. None of the above

102. The vice president plays a key role in the Upper House of Parliament. In this regard, consider the following statements:

1. He/she can cast a vote in the Rajya Sabha only in case of equality of votes.
2. He/she cannot preside over a sitting of the Rajya Sabha as its Chairman when a resolution for his removal is under consideration.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

103. How can the Speaker of the Lok Sabha be removed?

A. By a resolution passed by a two-thirds majority of the members of the Lok Sabha present.
B. By a resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha
C. By the President on the recommendation of the Prime Minister
D. By the Council Of minister on the recommendation of the Prime Minister

100. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. "स्वतंत्र पार्टी" प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी।
2. लोकसभा में "विपक्ष के नेता" को पहली बार वर्ष 1969 में मान्यता दी गई।
3. यदि किसी पार्टी के पास लोकसभा में न्यूनतम 75 सदस्य नहीं हैं, तो उसके नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3 B. केवल 2
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

101. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र सरकार की उधार सीमा भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है।
2. राज्य सरकार भारत के बाहर से उधार ले सकते हैं लेकिन भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ।
3. हाल ही में संसद ने केंद्र की उधार सीमा तय करने के लिए एक कानून बनाया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2 और 3
C. केवल 3 D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. संसद के उच्च सदन में उपराष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यसभा में केवल वोट बराबर होने की स्थिति में ही वह वोट दे सकता है।
2. जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता/सकती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

103. लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है?

A. लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा
B. लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा
C. प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा
D. प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद द्वारा

104. Consider the following statements about 'zero hour':

1. It is an Indian Parliamentary innovation.
2. It provides an opportunity for the MPs to raise national issues without advance notice.
3. It is available to members of both the Houses of the Parliament.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. Only 2 and 3 D. 1, 2 and 3

104. 'शून्य काल' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक भारतीय संसदीय नवप्रवर्तन है।
2. यह सांसदों को बिना अग्रिम सूचना के राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है।
3. यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

105. Consider the following statements regarding the exclusive powers of the Lok Sabha-

1. Ratifying the proclamation of emergency
2. Passing a no-confidence motion against the Council of Ministers
3. Impeachment of the President of India

Select the correct answer using the code given below:

A. 1 and 2 only B. 2 only
C. 1 and 3 only D. 3 only

105. लोकसभा की विशिष्ट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. केवल 3

106. Consider the following statements with respect to Municipalities:

1. It is not a constitutional obligation of the state to establish an urban local body in an industrial township.
2. All the members of a municipality shall be elected directly by the people of the municipal area.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

106. नगर पालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी औद्योगिक टाउनशिप में शहरी स्थानीय निकाय स्थापित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व नहीं है।
2. नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

107. Who among the following had a different portfolio in the first Cabinet of Independent India (1947) than the portfolio of his Interim Government (1946)?

1. Jagjivan Ram
2. Dr. Rajendra Prasad
3. C.H. Bhabha
4. Sardar Baldev Singh

Choose the correct options using the codes given below

A. 1 and 2 only B. 3 and 4 only
C. 1 and 3 only D. 3 only

107. स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (1947) में निम्नलिखित में से किनका संविभाग उनकी अंतरिम सरकार (1946) के संविभाग से अलग था?

1. जगजीवन राम
2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद
3. सी.एच. भाभा
4. सरदार बलदेव सिंह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए:

A. केवल 1 और 2 B. केवल 3 और 4
C. केवल 1 और 3 D. केवल 3

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

108. The Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution have been taken from the Constitution of which of the following countries?

A. United Kingdom

B. United States of America

C. Ireland

D. Japan

108. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

A. यूनाइटेड किंगडम

B. संयुक्त राज्य अमेरिका

C. आयरलैंड

D. जापान

109. With reference to the "Notified Area Committee", consider the following statements:

1. All its members are elected directly by the people.
2. It can be created for a fast-developing town due to industrialisation.
3. It is created as well as administered by the Central government.

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 and 2 Only

B. 2 Only

C. 2 and 3 Only

D. 1, 2 and 3

109. "अधिसूचित क्षेत्र समिति" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
2. इसे औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित होने वाला शहर बनाया जा सकता है।
3. इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया और प्रशासित किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 2 और 3

D. 1,2 और 3

110. Ad hoc judges are appointed in the Supreme Court when-

A. Some judges go on long-term leave

B. No one is available for a permanent appointment

C. There is an extraordinary increase in the cases pending before the court.

D. There is no quorum of judges for any session of the court.

110. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उस स्थिति में की जाती है, जब-

A. कुछ न्यायाधीश लंबी अवधि की छुट्टी पर चले जाते हैं

B. स्थाई नियुक्ति के लिए कोई न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं

C. न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है

D. न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है

111. Consider the following statements with reference to the "removal of Vice-President of India":

1. The motion for removal of the Vice-President can be initiated in either House of Parliament.
2. The charges for impeachment must be supported by a special majority in the initiating House.
3. Like the President of India, the Constitution provides specific grounds for the removal of the Vice-President of India.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1

B. Only 2 and 3

C. Only 3

D. None of the above

111. "भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2. महाभियोग के आरोपों को प्रस्ताव लाने वाले सदन में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है।
3. भारत के राष्ट्रपति की तरह, संविधान भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशिष्ट आधार का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 3

D. उपरोक्त में से कोई नहीं

112. Which of the following Directive Principles were added by the 42nd Constitution amendment?

1. To take steps to secure the participation of workers in the management of industries.
2. To protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife.
3. To secure opportunities for the healthy development of children.
4. To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor.

Select the correct answer using the code given below.

A. Only 1, 2 and 3 B. Only 1 and 3
C. Only 1, 2, and 4 D. 1, 2, 3 and 4

112. 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से निदेशक सिद्धांत जोड़े गए?

1. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
2. पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना।
3. बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना।
4. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1 और 3
C. केवल 1, 2, और 4 D. 1, 2, 3 और 4

113. Which jurisdiction gives the Supreme Court of India the authority to resolve conflicts between the Center and the States?

A. Appellate jurisdiction
B. Advisory jurisdiction
C. Constitutional jurisdiction
D. Original jurisdiction

113. कौन सा क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने का अधिकार देता है?

A. अपीलीय क्षेत्राधिकार
B. सलाहकार क्षेत्राधिकार
C. संवैधानिक क्षेत्राधिकार
D. मूल क्षेत्राधिकार

114. Which of the following directive principles is/are based on the Socialistic Principles?

1. Raise the level of nutrition and the standard of living of people and improve public health.
2. Promote equal justice and provide free legal aid to the poor.
3. To prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

114. निम्नलिखित में से कौन-सा/से निदेशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है/हैं?

1. लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।
2. समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
3. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

115. Consider the following statements regarding Directive Principles of State Policy:

1. It helps the courts to examine and determine a law's constitutional validity.
2. DPSPs are legally enforceable by the courts for their violation.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

115. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में मदद करता है।
2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) अपने उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

116. Which of the following options correctly represent the states in descending order based on seats in Rajya Sabha?

A. Gujarat > Karnataka > Kerala > Odisha
B. Karnataka > Gujarat > Kerala > Odisha
C. Karnataka > Gujarat > Odisha > Kerala
D. Gujarat > Karnataka > Odisha > Kerala

117. Consider the following statements about Writ Petition of ‘Quo Warranto’ filed in the High Court of a State:

1. It is issued to enquire into the legality of the claim of a person to a public office.
2. It cannot be filed by one who is not an aggrieved person.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

118. Essentially, “Due process of law” refers to?

A. Principle of natural justice
B. The method established by law
C. Fair application of the law
D. Equality before law

119. The Directive Principles of State policy have been useful to India because:

1. They serve as a crucial test for the performance of the government.
2. They have helped the courts in exercising their power of judicial review.
3. They serve as a common political manifesto.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3 D. 1, 2 and 3

120. With respect to the ‘unstarred question’ asked in the Parliamentary session, consider the following statements:

1. The answer to such a question is given orally.
2. The answer to such a question is not followed by supplementary questions.

Which of the statements given above is/are incorrect?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

116. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्यसभा में सीटों के आधार पर राज्यों के घटते क्रम को दर्शाता है?

A. गुजरात > कर्नाटक > केरल > ओडिशा
B. कर्नाटक > गुजरात > केरल > ओडिशा
C. कर्नाटक > गुजरात > ओडिशा > केरल
D. गुजरात > कर्नाटक > ओडिशा > केरल

117. किसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर ‘अधिकार पृच्छा’ रिट याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है।
2. यह उस व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता जो पीड़ित व्यक्ति नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

118. मूलतः, “विधि की सम्यक प्रक्रिया” से तात्पर्य है?

A. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
B. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
C. कानून का उचित अनुप्रयोग
D. विधि के समक्ष समानता

119. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि:

1. वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं।
2. उन्होंने अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में मदद की है।
3. वे एक आम राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3 D. 1, 2 और 3

120. संसदीय सत्र में पूछे जाने वाले ‘अतारांकित प्रश्न’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऐसे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
2. ऐसे प्रश्न के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

121. Which one of the following committees suggested that 'the Governor should be an eminent person from outside the state, and should be a neutral person who does not have deep political affiliations or has not participated in politics in recent years'?

A. First Administrative Reforms Commission (1966)
B. Rajamannar Committee (1969)
C. Sarkaria Commission (1983)
D. National Commission to Review the Working of the Constitution (2000)

122. The Constitution empowers the Parliament to make laws on any matter enumerated in the State List under extraordinary circumstances. In this regard, consider the following statements:

1. The Parliament can enact laws on a matter in the State List if the legislature of one state passes resolutions requesting the Parliament to do so.
2. Such a law can be amended or repealed by the legislatures of the concerned states.
3. Not a single law has been passed so far under this provision.

How many of the above statements is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Only 3 D. None

123. Which of the following steps are included in general financial legislation?

1. Presentation of the budget
2. Discussion on budget
3. Passing the Appropriation Bill
4. Vote on Account
5. Passing the Finance Bill

Select the correct options using the codes given below-

A. 1, 2 and 3 only B. 1, 3 and 4 only
C. 1, 2, 3 and 4 only D. 1, 2, 3 and 5 only

124. Which DPSP was added by the 97th Amendment to the Constitution?

A. Equal pay for equal work for both men and women.
B. Participation of workers in the management of industries.
C. Promotion of cooperative societies.
D. Securing living wage and human conditions of work for workers.

121. निम्नलिखित में से किस समिति ने सुझाव दिया कि 'राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, और एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी घनिष्ठ राजनीतिक संबद्धता न हो या जिसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो'?

A. प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)
B. राजमन्नार समिति (1969)
C. सरकारिया आयोग (1983)
D. संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2000)

122. संविधान संसद को असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संसद राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बना सकती है यदि एक राज्य की विधायिका संसद से ऐसा करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करती है।
2. ऐसे कानून को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।
3. इस प्रावधान के तहत अब तक एक भी कानून पारित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. कोई भी नहीं

123. निम्नलिखित में से कौन से चरण सामान्य वित्तीय विधायन में शामिल हैं?

1. बजट पेश करना
2. बजट पर चर्चा करना
3. विनियोग विधेयक पारित करना
4. लेखानुदान
5. वित्त विधेयक पारित करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए-

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 1, 2, 3 और 4 D. केवल 1, 2, 3 और 5

124. संविधान में 97वें संशोधन द्वारा कौन-सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) जोड़ा गया?

A. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन।
B. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।
C. सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
D. श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी और काम की मानवीय स्थितियाँ सुरक्षित करना।

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

125. Which of the following statements regarding Lok Adalats are correct?

1. There is no court fee and if the court fee is already paid the amount will be refunded if the dispute is settled at Lok Adalat.
2. There is no strict application of procedural laws like the Civil Procedure Code and the Evidence Act while assessing the claim by Lok Adalat.
3. The parties to the dispute can directly interact with the judge through their counsel which is not possible in regular courts of law.
4. The award by the Lok Adalat is binding on the parties.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1, 2 and 3 B. Only 2 and 4
C. Only 1, 3 and 4 D. 1, 2, 3 and 4

125. लोक अदालतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इसके लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी।
2. लोक अदालत द्वारा दावे का मूल्यांकन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।
3. विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
4. लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

A. केवल 1, 2 और 3 B. केवल 2 और 4
C. केवल 1, 3 और 4 D. 1, 2, 3 और 4

126. "To protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country." is a provision made in the

A. Preamble of the Constitution
B. Directive Principles of State Policy
C. Fundamental Duties
D. Both B and C

126. "पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है:

A. संविधान की प्रस्तावना में
B. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में
C. मौलिक कर्तव्य में
D. B और C दोनों

127. Regarding the composition of the Legislative Council in a State, which of the following statements is/are correct?

1. A Legislative Council cannot have more than one-third members of the total strength of the Legislative Assembly of that State.
2. The Legislative Council of a state must have at least Forty members.

Select the correct answer from the code given below-

A. 1 only B. 2 Only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

127. किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. किसी विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते।
2. किसी राज्य की विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होना अनिवार्य है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

128. Consider the following statements:

1. If there is a conflict between the Concurrent List and the State List, the State List prevails.
2. The power to levy residuary taxes lies with the respective state government.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

128. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है, तो राज्य सूची मान्य होती है।
2. अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकार के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

129. Which of the following constitutes the revenue of the urban local bodies?

1. Local taxes include property tax and entertainment tax.
2. User charges include water charges, sanitation charges, and sewerage charges.
3. Various cess like library cess, education cess, beggary cess.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 and 2
B. Only 2 and 3
C. Only 1 and 3
D. All of the above

129. शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व निम्नलिखित में से किससे बनता है?

1. स्थानीय करों में संपत्ति कर और मनोरंजन कर शामिल हैं।
2. उपयोगकर्ता शुल्क में जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, सीवरेज शुल्क शामिल हैं।
3. विभिन्न उपकर जैसे पुस्तकालय उपकर, शिक्षा उपकर, भिक्षावृत्ति उपकर।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपर्युक्त सभी

130. Match the list-I with List II:

List-I	List-II
a. Constitution of Legislature in the States	(i) Article 178
b. Speaker and Deputy Speaker in the Legislative Assembly	(ii) Article 199
c. Salaries and allowances of members	(iii) Article 168
d. Definition of 'Money Bill'	(iv) Article 195

Choose the correct option using the codes given below-

A. a-i b-ii c-iii d-iv
B. a-iv b-ii c-i d-iii
C. a-iii b-i c-iv d-ii
D. a-ii b-iii c-i d-iv

130. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
a. राज्यों में विधानमंडल का गठन	(i) अनुच्छेद 178
b. विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	(ii) अनुच्छेद 199
c. सदस्यों के वेतन एवं भत्ते	(iii) अनुच्छेद 168
d. 'धन विधेयक' की परिभाषा	(iv) अनुच्छेद 195

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए-

A. a-i b-ii c-iii d-iv
B. a-iv b-ii c-i d-iii
C. a-iii b-i c-iv d-ii
D. a-ii b-iii c-i d-iv

131. Consider the following statements about the 'Gram Nyayalaya':

1. It is a mobile court.
2. It exercises the powers of only Civil Courts and not of Criminal Courts.
3. It tries to settle the disputes as far as possible by bringing conciliation between the parties.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1
B. Only 2
C. Only 2 and 3
D. Only 1 and 3

131. 'ग्राम न्यायालय' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक चलित न्यायालय है।
2. यह केवल सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, न कि आपराधिक न्यायालय की।
3. यह पक्षों के बीच सुलह कराकर यथासंभव विवादों को निपटाने का प्रयास करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 2 और 3
D. केवल 1 और 3

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

132. Consider the following statements:

1. The Central Information Commission is a high-powered independent body.
2. The Central Information Commission is a constitutional body.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

132. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है।
2. केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक संस्था है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

133. Consider the following statements-

1. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his/her office if he/she ceases to be a member of the Legislative Assembly.
2. Whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall forthwith vacate his/her office.

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 Only B. 2 Only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

133. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, तो उसे अपना पद छोड़ना होता है।
2. जब भी विधानसभा भंग की जाती है, तो अध्यक्ष को तत्क्षण अपना पद छोड़ना होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

134. With reference to the pardoning power of the Governor, consider the following statements:

1. He cannot pardon a death sentence.
2. He can pardon a death sentence if a state law prescribes for death sentence.
3. He can suspend, remit or commute a death sentence.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Only 1 and 3 D. Only 2 and 3

134. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता।
2. यदि राज्य के कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है तो वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है।
3. वह मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 1 और 3 D. केवल 2 और 3

135. The independence of the Supreme Court becomes very essential for the effective discharge of the duties assigned to it. Which of the following provisions ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court?

1. Security of tenure
2. Ban on Practice after Retirement
3. Power to Punish for its Contempt
4. Its Jurisdiction cannot be Curtailed

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1, and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 1, 2 and 3 D. 1, 2, 3 and 4

135. सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए उसकी स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है?

1. कार्यकाल की सुरक्षा
2. रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पर रोक
3. अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति
4. इसके अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 1, 2 और 3 D. 1, 2,3 और 4

136. Consider the following statements-

1. Judicial custody means that the accused is in the custody of the concerned Magistrate and such accused is kept in the lock-up of the police station and not in jail.
2. During judicial custody, the police officer in charge of the case cannot interrogate the suspect without the permission of the Court.

Which of the statements given above is/are correct?

A. 1 Only B. 2 Only
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

136. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोपी को पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में रखा जाता है, न कि जेल में।
2. न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी अदालत की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

137. The writ jurisdiction of the Supreme Court differs from that of a High Court in which of the following respects?

1. Unlike a High Court, the Supreme Court can issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights but also for any other purpose.
2. The Supreme Court can issue writs against a person throughout the territory of India whereas a High Court cannot issue writs outside its territorial jurisdiction.
3. Unlike the Supreme Court, a High Court may refuse to exercise its writ jurisdiction.

Select the correct answer using the code given below:

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. Only 3 D. Only 2 and 3

137. सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय से भिन्न है?

1. उच्च न्यायालय के विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है जबकि एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर रिट जारी नहीं कर सकता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत, एक उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 3 D. केवल 2 और 3

138. Which of the following does not necessarily follow from a state's declaration of the president's rule?

1. Dissolution of the State Assembly
2. Removal of the Council of Ministers of the State
3. Dissolution of local bodies

Select the correct answer using the code given below-

A. 1 and 2 only B. 1 and 3 only
C. 2 and 3 only D. 1, 2 and 3

138. निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अनुसरण नहीं है?

1. राज्य विधानसभा का विघटन
2. राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना
3. स्थानीय निकायों का विघटन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

139. Which of the following committees is only formed in the Lok Sabha?

A. Committee on Assurances
B. Estimates Committee
C. Committee on Public Undertakings
D. Committee on Delegated Legislation

139. निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल लोकसभा में गठित होती है?

A. आश्वासन समिति
B. प्राक्कलन समिति
C. सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
D. प्रत्यायोजित विधान पर समिति

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com

140. Which of the following are enumerated in the concurrent list?
1. Education
2. Forests
3. Defence
4. Banking
5. Prisons

Select the correct answer using the code given below:
- A. Only 1 and 2
- B. Only 2 and 3
- C. Only 3 and 4
- D. Only 4 and 5

140. निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में गिना जाता है?
1. शिक्षा
2. वन
3. रक्षा
4. बैंकिंग
5. कारागार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 3 और 4
- D. केवल 4 और 5

141. Which of the following amendments of the Constitution provided for the establishment of a common High Court for two or more states?
- A. Fifth Amendment Act, 1955
- B. Seventh Amendment Act, 1956
- C. Tenth Amendment Act, 1961
- D. Fourteenth Amendment Act, 1962

141. संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया?
- A. पाँचवाँ संशोधन अधिनियम, 1955
- B. सातवां संशोधन अधिनियम, 1956
- C. दसवां संशोधन अधिनियम, 1961
- D. चौदहवाँ संशोधन अधिनियम, 1962

142. **Assertion (A):** The Court can review the advice given by the Ministers to the Governor.

Reason (R): There is no legal accountability for state ministers in the Indian Constitution.

Which of the following is correct in the context of the above two statements?
- A. Both Assertion (A) and Reason (R) are correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- B. Both Assertion (A) and Reason (R) are correct, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- C. Assertion (A) is correct, but reason (R) is wrong.
- D. Assertion (A) is false, but Reason (R) is correct.

142. **अभिकथन (A)-** न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा कर सकता है।

कारण (R)- भारतीय संविधान में राज्य मंत्रियों के लिए कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है।

उपर्युक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
- A. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- B. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- C. अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
- D. अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

143. Consider the following statements:
1. The laws of the Parliament are applicable to Indian citizens and their property in any part of the world.
2. The President is empowered to direct that an act of Parliament does not apply to a scheduled area in the state.

Which of the above statements is/are correct?
- A. Only 1
- B. Only 2
- C. Both 1 and 2
- D. Neither 1 nor 2

143. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं।
2. राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. 1 और 2 दोनों
- D. न तो 1 और न ही 2

144. Consider the following statements:

1. An unstarred question requires an oral answer and hence supplementary questions can follow.
2. A starred question, on the other hand, requires a written answer and hence, supplementary questions cannot follow.

Which of the statements given above is/are correct?

A. Only 1 B. Only 2
C. Both 1 and 2 D. Neither 1 nor 2

145. Consider the following statement regarding the National Human Rights Commission(NHRC)-

1. It is a Constitutional body
2. It came into existence in 1997
3. Its Chairperson should compulsorily be a Retired chief justice of the Supreme Court or High court

Which of the statements given above are correct?

A. Only 1 B. Only 1 and 2
C. Only 3 D. None of the above

146. Consider the following statements with reference to the "Attorney General of India":

1. He/she can participate in the proceedings of the Parliament, but cannot vote on any matter.
2. He/she is eligible for reappointment for multiple terms, subject to the pleasure of the President.
3. He/she has the authority to grant pardons in a few cases.

Which of the above statements is/are correct?

A. Only 1 and 2 B. Only 2 and 3
C. Only 2 and 3 D. 1, 2 and 3

147. Parliament has no role in removing which of the following officials?

1. High Court judges
2. Judges of the Supreme Court
3. Chairman, Union Public Service Commission
4. Comptroller and Auditor General of India

Select the correct answer from the codes given below.

A. 1 and 2 Only B. 3 and 4 Only
C. 1, 2 and 3 Only D. 3 Only

144. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
2. दूसरी ओर, तारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1, न ही 2

145. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक संवैधानिक संस्था है।
2. यह 1997 में अस्तित्व में आया।
3. इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 1 और 2
C. केवल 3 D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

146. "भारत के महान्यायवादी" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता/सकती है, लेकिन किसी मामले पर मतदान नहीं कर सकता सकती है।
2. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त, कई कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होती/होती है।
3. उसके पास कुछ मामलों में क्षमादान देने का अधिकार होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. केवल 2 और 3 D. 1, 2 और 3

147. इनमें से किस अधिकारी को उसके पद से हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं है?

1. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

A. केवल 1 और 2 B. केवल 3 और 4
C. केवल 1, 2 और 3 D. केवल 3

KGS Campus, Near Sai Mandir, Musallahpur Koiritola, Patna, Bihar-800006
Call : 8757354880, E-mail: enquiry@khanglobalstudies.com
KGS IAS

148. **Assertion (A):** The President of India decides the qualifications of the Chairman and members of the Finance Commission.

Reason (R): The Chairman and members are appointed by the President of India.

Select the correct answer with the help of the code given below.

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

C. (A) is true, but (R) is false.

D. (A) is wrong, but (R) is true.

148. **अभिकथन (A)-**भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएँ निर्धारित करते हैं।

कारण (R)- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

A. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।

B. अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।

C. अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।

D. अभिकथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

149. Consider the following statements:

1. The judges of the Supreme Court are appointed by the Chief Justice of India.
2. The judges of the Indian Judiciary are selected through the National Judicial Appointment Commission.
3. The earlier collegium system of appointment of judges has been struck down as ultra vires.

Which of the above statements is/are correct?

A. Only 1

B. Only 2 and 3

C. Only 1 and 3

D. None of the above

149. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
2. भारतीय न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से किया जाता है।
3. न्यायाधीशों की नियुक्ति की पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. उपर्युक्त में से कोई नहीं

150. In 1988, the "Thungon Committee" suggested measures for the strengthening of the Panchayati Raj system. Which of the following are suggested by the Thungon committee?

1. A three-tier system of Panchayati Raj with panchayats at the village, block and district levels.
2. Zilla Parishad should be the pivot of the Panchayati Raj system.
3. Reservation for women is not required.
4. The Chief Minister should be the chief executive officer of the Zilla Parishad.

Select the correct answer using the code given below:

A. 1 and 2 Only

B. 2 and 3 Only

C. 3 and 4 Only

D. 1 and 4 Only

150. 1988 में "थुंगन समिति" ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाए थे। थुंगन समिति ने निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिया है?

1. गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली।
2. जिला परिषद् को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बनाना चाहिए।
3. महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
4. मुख्यमंत्री को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए-

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 3 और 4

D. केवल 1 और 4

BPSC TEST - 1 (SOLUTIONS)

Q 1. उत्तर: A

व्याख्या:

चार्टर अधिनियम, 1813 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी (चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा) के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को भी मजबूत किया गया।

हालाँकि इस अधिनियम के माध्यम से अगले 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों के अधिकार और राजस्व को कंपनी को सौंप दिया गया, लेकिन यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के विपरीत नहीं था।

1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत के राजस्व को ब्रिटिश संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन राज्य सचिव का पद सृजित किया गया और, विशेष रूप से, राजस्व के प्रशासन में उनकी सहायता के लिए भारतीय परिषद का गठन किया गया।

Q 2. उत्तर: A

व्याख्या

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान किया गया है। पूर्ण वीटो विधेयक पर सहमति को रोक कर रखने की राष्ट्रपति की शक्ति है।

राष्ट्रपति निम्नलिखित दो मामलों में पूर्ण वीटो का उपयोग करता है:

- ✓ जब संसद द्वारा पारित विधेयक एक निजी विधेयक हो।
- ✓ जब कैबिनेट राष्ट्रपति के विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले इस्तीफा दे देती है तो नई कैबिनेट राष्ट्रपति को पुरानी कैबिनेट द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे सकती है।

निलंबित वीटो का उपयोग पहली बार संसद द्वारा पारित लाभ के पद विधेयक, 2006 में किया गया था। इसमें एक स्व-सेवारत कानून निर्मित करने का प्रावधान था जो सदस्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव से अयोग्यता से सुरक्षा प्रदान करता था। राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने इस विधेयक को लौटा दिया था। हालांकि, विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा गया और अंततः मंजूरी मिली।

Q 3. उत्तर C

व्याख्या:

1992 में 73 वें संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची (पंचायतों के दायरे में 29 विषयों को शामिल करने वाली) और ₹पंचायतें₹ नामक एक नए भाग IX (अनुच्छेद 243 (A) से 243 (O) तक के प्रावधानों को कवर करने वाले) को जोड़ा गया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) और सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) के संचालन की समीक्षा करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए जनवरी 1957 में एक समिति की स्थापना की।

इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति के अनुसार, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव हैं। इन स्तरों को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव तंत्र से जोड़ा जाना चाहिए।

बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में ग्राम सभा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

Q 4. उत्तर: A

व्याख्या:

महात्मा गांधी ने 1939 में हरिजन पत्रिका में अपने लेख 'द ओनली वे' में लिखा कि "संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है।"

Q 5. उत्तर: A

व्याख्या:

संविधान के तहत, किसी व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा:

- ✓ यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद धारण करता है (किसी मंत्री या राज्य विधायिका द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य पद को छोड़कर)।
- ✓ यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
- ✓ यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
- ✓ यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा के पालन की किसी स्वीकृत प्रतिज्ञा के अधीन है।
- ✓ यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।

Q 6. उत्तर: A

व्याख्या:

प्रश्न में दी गई गतिविधियों का सही कालक्रम इस प्रकार है:

- ✓ संविधान सभा की प्रथम बैठक - 9 दिसम्बर 1946
- ✓ प्रारूप समिति की नियुक्ति- 29 अगस्त 1947
- ✓ भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया - 26 नवंबर, 1949
- ✓ भारत के संविधान के लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 है

Q 7. उत्तर: D

व्याख्या:

राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है:

- ✓ कार्यकारी शक्तियाँ
- ✓ विधायी शक्तियाँ
- ✓ वित्तीय शक्तियाँ
- ✓ न्यायिक शक्तियाँ

इसके अलावा, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसके सम्बन्ध में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य नहीं होता/होती है।

किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, राज्य वित्त आयोग (243-आई) की संरचना, उसके सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं और उनके चयन के तरीके के बारे में प्रावधान कर सकता है।

Q 8. उत्तर. B

व्याख्या:

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या भौतिक पहलुओं से कहीं अधिक को शामिल करते हुए की है। इसमें अब सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जो निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करता है:

- ✓ भोजन, वस्त्र और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के साथ जीने का अधिकार
- ✓ स्वास्थ्य का अधिकार
- ✓ शिक्षा का अधिकार
- ✓ स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार

कई निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आश्रय का अधिकार और आजीविका का साधन जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है क्योंकि इन आवश्यकताओं के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है।

Q 9. उत्तर: C

व्याख्या:

भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना थी।

इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया - 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित'।

आरक्षित विषयों में न्याय प्रशासन, भू-राजस्व, वित्त, पुलिस आदि से संबंधित मामले शामिल थे, जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि से संबंधित मामले शामिल थे।

आरक्षित विषयों को प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जबकि हस्तांतरित विषयों को गवर्नर और मंत्रिपरिषद के अधीन रखा गया था जो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे।

Q 10. उत्तर: B

व्याख्या:

संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं:

- ✓ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
- ✓ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- ✓ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

Q 11. उत्तर: A

व्याख्या:

राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे।

राज्य विधायिका नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकती है।

यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालाँकि, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है।

Q 12. उत्तर: D

व्याख्या:

न्यायिक सक्रियता को ‘न्यायिक गतिशीलता’ के नाम से भी जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है।

दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य सरकार के अन्य दो अंगों (विधायिका और कार्यपालिका) को अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य करने में न्यायपालिका की मुखर भूमिका से है।

Q 13. उत्तर: A

व्याख्या:

अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि कर लगाने वाला विधेयक या संशोधन केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश या प्रस्तावित किया जाएगा और ऐसा प्रावधान करने वाला विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा।

Q 14. उत्तर: B

व्याख्या:

राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों को नामांकित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन ऐसे नामांकन उस पंचायत में चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होंगे।

प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं।

नीलामी/बोली द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत देने हेतु ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

Q 15. उत्तर: B

व्याख्या

विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा देता है।

विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है।

Q 16. उत्तर: B

व्याख्या:

सही सुमेल इस प्रकार है:

- ✓ संविधान का भाग XV - निर्वाचन
- ✓ संविधान का भाग XVI - कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान
- ✓ संविधान का भाग XVII - राजभाषा
- ✓ संविधान का भाग XVIII - आपातकालीन प्रावधान

Q 17. उत्तर: D

व्याख्या:

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय (चाहे विशिष्ट या सामान्य) में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझता है। इस प्रकार, संविधान उच्च न्यायालय की सदस्य संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ता है।

Q 18. उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय संविधान की उद्देशिका का लक्ष्य है अपने सभी नागरिकों की -

- ✓ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना
- ✓ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- ✓ स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करना
- ✓ व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना

Q 19. उत्तर: B

व्याख्या

परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है - 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।

परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Q 20. उत्तर: D

व्याख्या:

जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, भारत का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है।

किसी भी समय, भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अस्थायी अवधि के लिए. न्यायाधीश ऐसे भत्तों का हकदार होता है जो राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है।

Q 21. उत्तर: C

व्याख्या:

जब कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह केवल विधेयक को अनुमोदन दे सकता है और विधेयक को अस्वीकार या वापस नहीं कर सकता है।

जब कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और वह विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है और जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक पर अपनी सहमति दे दे या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, लेकिन विधेयक को सदन को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता।

Q 22. उत्तर: C

व्याख्या:

संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार चर्चा की गई है। इसे निम्नलिखित मामलों के माध्यम से समझा जा सकता है:

- ✓ बेरुबारी मामला: इस वाद में बेरुबारी संघ से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत एक संदर्भ शामिल था, जिस पर आठ न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया था। न्यायालय ने कहा कि "प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को जानने की कुंजी है" लेकिन निष्कर्ष निकाला कि इसे संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
- ✓ केशवानंद भारती मामला: इस ऐतिहासिक मामले में, एक रिट याचिका पर सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों की एक पीठ बुलाई गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना वास्तव में संविधान का भाग है। हालाँकि यह सर्वोच्च शक्ति या किसी प्रतिबंध या निषेध का स्रोत नहीं है, यह संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ✓ एलआईसी ऑफ इंडिया मामला 1995: सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, हालांकि यह भारत के न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

Q 23. उत्तर: A

व्याख्या

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) की स्थापना 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी और इसे 1920 के संसद अधिनियम XV के तहत शामिल किया गया था। इस अधिनियम को अंतिम बार 1992 में संशोधित किया गया था और 1994 में नियम बनाए गए थे। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है, जिसका देश भर में 1100 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है, जो आपदाओं/आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है तथा कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है।

भारत के माननीय राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं।

Q 24. उत्तर: B

व्याख्या:

'न्यायालय की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसको 1971 के न्यायालय अवमानना अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके तहत न्यायालय की अवमानना दीवानी या आपराधिक हो सकती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है।

अवमानना क्षेत्राधिकार का उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना है। अवमानना शक्तियां न्यायाधीशों को भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना मामलों का निर्णय करने के अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती हैं।

Q 25. उत्तर: A

व्याख्या:

प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा नौवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31-A और 31-B को संविधान में जोड़ा गया था।

विशेष कानूनों (जैसे भूमि सुधार कानून) को संसद द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक समीक्षा से मुक्त होना है।

अनुच्छेद 31B में कहा गया है कि नौवीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वे भाग III के किसी भी प्रावधान और प्रदत्त अधिकारों के साथ असंगत हैं, या उन्हें हटाते या कम करते हैं। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु मामले में यह स्पष्ट किया कि संसद को नौवीं अनुसूची में एक विशेष कानून डालने का अधिकार है, लेकिन यह न्यायिक जांच के दायरे से बाहर नहीं है।

न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती मामले के फैसले की तारीख) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल विधानों की इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि वे संविधान की मूल संरचना की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं।

Q 26. उत्तर: B

व्याख्या:

न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति है।

इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद 1975 में, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूल संरचना का एक तत्व घोषित किया।

संविधान की सर्वोच्चता, संघीय संतुलन को बनाए रखने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।

Q 27. उत्तर: A

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। हटाने का आधार दुर्व्यवहार और अक्षमता या दोनों का सिद्ध होना है।

100 सदस्यों (लोकसभा के मामले में) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के मामले में) द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव अध्यक्ष/सभापति को दिया जाता है।

अध्यक्ष/सभापति निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं।

Q 28. उत्तर: D

व्याख्या:

अनुच्छेद 153 के तहत, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 158(2) के तहत, राज्यपाल लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

अनुच्छेद 161 के तहत, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गये किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी ।

अनुच्छेद 165 के तहत, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।

Q 29. उत्तर: D

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: सभी उच्च न्यायालय नहीं, केवल तीन उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए थे। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।

कथन 2 गलत है: चंद्र कुमार मामले (1997) में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का रिट क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का एक भाग है। इसलिए, इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से भी हटाया नहीं जा सकता है।

कथन 3 गलत है: संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है। किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के प्रस्ताव की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए जिसकी राय इस संबंध में निर्णायक हो।

Q 30. उत्तर: A

व्याख्या:

मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में इसके विशिष्ट तत्व आज भी मूर्त रूप में विद्यमान हैं। हालाँकि, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो विभिन्न युगों से लगातार बदल रही है, में आधुनिक शैली, पारंपरिक शैली और संत शैली के तत्व शामिल हैं। यह स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की पुष्टि करता है।

Q 31. उत्तर: A

व्याख्या:

संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब केवल एक सदन का सत्र चल रहा हो क्योंकि कोई भी कानून दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है न कि केवल एक सदन द्वारा।

कूपर मामले (1970) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। 1975 के 38 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक और न्यायिक समीक्षा से परे बना दिया। लेकिन, इस प्रावधान को 1978 के 44 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया था। इस प्रकार, राष्ट्रपति की संतुष्टि को दुर्भावना के आधार पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है।

यदि अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो यह एक अधिनियम बन जाता है। यदि संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के छह सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो अध्यादेश निर्धारित छह सप्ताह से पहले भी लागू नहीं हो सकता है।

Q 32. उत्तर: A

व्याख्या:

निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले किसी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी।

इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की समाप्ति तक पंचायतों से संबंधित सभी राज्य कानून लागू रहेंगे।

ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाएंगे।

Q 33. उत्तर: D

व्याख्या:

परिभाषा के अनुसार संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार है।

इसका अर्थ है कि संविधान सरकार का स्रोत है और इसके तीन अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, संविधान में निहित प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं।

संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएँ इतनी मौलिक हैं कि सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

Q 34. उत्तर: A

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन होगा।

कथन 2 सही है: ग्राम न्यायालय एक गतिशील न्यायालय होगा और आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियों का प्रयोग करेगा। ग्राम न्यायालय की सीट मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होगी, वे गांवों में जाएंगे, वहां काम करेंगे और मामलों का निपटारा करेंगे।

कथन 3 सही है: ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और इसके पीठासीन अधिकारी को उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

Q 35. उत्तर: B

व्याख्या:

संविधान-पूर्व संधि से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सलाह राष्ट्रपति को देनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं होती है । इसलिए, यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है; वह सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी ।

सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य जिस पर प्रश्न उठा हो या उठने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है।

Q 36. उत्तर: C

व्याख्या:

वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 (1) में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है। साथ ही, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है।

Q 37. उत्तर: B

व्याख्या:

कथन 1 और 2 सही है: राष्ट्रपति के निर्वाचन और महाभियोग तथा राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के अनुमोदन में, राज्यसभा की शक्तियाँ और स्थिति लोकसभा के बराबर होती है।

कथन 3 गलत: राज्यसभा बजट पर केवल चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती (जो लोकसभा का विशेष विशेषाधिकार है)।

Q 38. उत्तर: B

व्याख्या:

भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है।

यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के समान है।

इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

Q 39. उत्तर: A

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार निम्नलिखित तक विस्तारित नहीं है:

किसी संविधान-पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा, अनुबंध, सनद या अन्य समान दस्तावेज़ से उत्पन्न विवाद।

केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशन का समायोजन।

एक संघीय न्यायालय के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का निर्णय करता है। विस्तृत रूप से निम्नलिखित मामलों में

- ✓ केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच
- ✓ एक तरफ केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के बीच तथा दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच
- ✓ दो या दो से अधिक राज्यों के बीच.

Q 40. उत्तर: C

व्याख्या:

मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्च न्यायालय की पहली बार में विवादों को सुनने की शक्ति, न कि अपील के माध्यम से। इसका विस्तार निम्नलिखित तक है:

कथन 1 सही है: नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, न्यायालय की अवमानना के मामले।

कथन 2 सही है: संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।

कथन 3 सही है: संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देना।

Q 41. उत्तर: B

व्याख्या:

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपों को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिनका 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया।

दिसंबर, 1961 में, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली प्रभुत्व से भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया और मार्च, 1962 में संसद द्वारा अधिनियमित 12 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा राज्य के गठन के साथ, दमन और दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए।

1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

दादरा और नगर हवेली को 10 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1961 द्वारा 11 अगस्त 1961 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया था।

नोट- केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को 26 जनवरी, 2020 से विलय कर दिया गया।

Q 42. उत्तर: C

व्याख्या:

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के अनिवार्य प्रावधानः
- ✓ किसी गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का गठन
- ✓ ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन
- ✓ राज्य चुनाव आयोग की स्थापना.

कथन 2 गलत हैः तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) के स्वैच्छिक प्रावधानः
- ✓ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति का निर्धारण करना।
- ✓ राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना।
- ✓ राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायत को सौंपना

Q 43. उत्तर: C

व्याख्या

राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के एक-चौथाई सदस्यों (जिन्होंने आरोप तय किए) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए।

उस सदन की कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।

महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रकृति को दर्शाता है क्योंकि यह विधायी और न्यायिक दोनों प्रकृति को दर्शाता है।

Q 44. उत्तर: A

व्याख्या

युग्म 1 सही हैः जब राष्ट्रपति 'विराम' का उपयोग करता है, तो वह मूल सजा के स्थान पर कम सजा देने का विकल्प चुनता है

युग्म 2 गलत हैः जब राष्ट्रपति परिहार का उपयोग करता है, तो वह सजा की अवधि को कम करने के लिए कार्य करता है, लेकिन सजा की प्रकृति वही रहती है।

युग्म 3 गलत हैः जब राष्ट्रपति 'प्रविलंबन' का उपयोग करता है; तो वह किसी सजा (विशेषकर मौत की सजा) के निष्पादन पर अस्थायी अवधि के लिए रोक लगा देता है। ऐसा करने से, वह दोषी को उससे क्षमा मांगने या सजा कम करने के लिए समय देता है।

Q 45. उत्तर: D

व्याख्या:

चंपकम दोराइराजन वाद, 1951 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, मौलिक अधिकार की प्रधानता होगी।

के.एस. पुट्टास्वामी वाद, 2018 में न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों में गारंटीकृत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है, और यह गरिमा, स्वायत्तता और स्वतंत्रता का आंतरिक पहलू है। यह मामला सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच विवाद/संघर्ष से संबंधित नहीं था।

केशवानंद भारती मामले, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने गोलकनाथ (1967) फैसले को खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह इसकी "मूल संरचना" को नहीं बदल सकती है।

गोलकनाथ मामले, 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

Q 46. उत्तर: D

व्याख्या:

मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता हैः
- ✓ ये राष्ट्रविरोधी और असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।
- ✓ ये किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालतों की मदद करते हैं। मोहन कुमार सिंघानिया मामले (1991) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्तव्य) का उपयोग उनकी संवैधानिकता निर्धारित करने हेतु अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है।
- ✓ ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। ये यह भावना पैदा करते हैं कि नागरिक केवल दर्शक नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं।
- ✓ ये कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं। इसलिए, संसद उनमें से किसी को पूरा करने में विफलता के लिए उचित जुर्माना या सजा लगाने का प्रावधान कर सकती है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 जैसे कई कानून राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को दंडनीय कृत्य बनाते हैं।

Q 47. उत्तर: D

व्याख्या:

29 दिसंबर, 1953 को भारत सरकार ने राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।

इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 1956 में संसद द्वारा अधिनियमित राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया।

न्यायमूर्ति फजल अली (आयोग के अध्यक्ष) के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे।

इस आयोग ने मुंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया।

Q 48. उत्तर: C

व्याख्या:

अनुच्छेद 47 के तहत, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होगा।

अनुच्छेद 51A के तहत, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि-
- ✓ संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना,
- ✓ स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना ,
- ✓ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए,
- ✓ देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना,

- ✓ धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना।
- ✓ देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना ,
- ✓ वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना,
- ✓ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना ,
- ✓ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना,
- ✓ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके, और
- ✓ छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

Q 49. उत्तर: C

व्याख्या:

भारत के महान्यायवादी को सरकार का कानून अधिकारी माना जाता है और देश की सभी अदालतों में इसे सुनवाई का अधिकार होता है। इसका मतलब यह है कि वह सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उसे सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में सरकार की ओर से उपस्थित होने और दलील देने का विशेषाधिकार है।

भारत के महान्यायवादी को पद पर रहते हुए निजी कानूनी प्रैक्टिस में शामिल होने की अनुमति है, और निजी प्रैक्टिस से अर्जित कोई भी फीस अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा करने के लिए प्राप्त वेतन से अलग है। यह प्रावधान अटॉर्नी जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस जारी रखने की अनुमति देने के लिए है।

उन्हें वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति प्राप्त हैं जो एक संसद सदस्य को उपलब्ध हैं।

Q 50. उत्तर: C

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था शालीनता या नैतिकता, या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के आधार पर नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को युक्तियुक्त रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

Q 51. उत्तर: C

व्याख्या:

अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू रहती है तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं।

इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को वित्त हस्तांतरण (कर साझाकरण और सहायता अनुदान दोनों) को कम या रद्द कर सकता है।

Q 52. उत्तर: C

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: उपराष्ट्रपति का चुनाव वास्तव में एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, न कि राज्यों की विधानसभाओं के।

कथन 2 गलत है: उपराष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही के माध्यम से नहीं, बल्कि राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

Q 53. उत्तर: A

व्याख्या:

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट (1928) द्वारा किया गया था, इसलिए विकल्प (A) सही उत्तर है।

Q 54. उत्तर: D

व्याख्या:

संसद ने किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में निम्नलिखित अतिरिक्त योग्यताएं निर्धारित की हैं:

विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए।

राज्यपाल के नामांकन के लिए योग्य व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए।

विधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।

Q 55. उत्तर: D

व्याख्या:

अनुच्छेद 41 के तहत राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43 A के तहत राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 43 के तहत, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

Q 56. उत्तर: A

व्याख्या:

धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं।

विधान परिषद केवल बजट पर चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती।

राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के संबंध में राज्य विधान परिषद, राज्य विधान सभा के साथ समान शक्ति साझा करती है।

Q 57. उत्तर: D

व्याख्या:

संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। हालाँकि, इसकी विषय वस्तु और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अर्थात, समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक।

निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को शामिल करना है। नीति निर्देशक तत्व देश में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकारों से होती है।

Q 58. उत्तर: B

व्याख्या:

पैरोल किसी कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है। यह रिहाई आमतौर पर कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि के लिए सशर्त होती है और उसे समय-समय पर अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

पैरोल (या फरलो) का उद्देश्य जेल प्रणाली को मानवीय बनाना है और यह 1894 के जेल अधिनियम के तहत शासित होता है। पैरोल किसी कैदी का अधिकार नहीं है और यह केवल किसी विशेष कारण या परिस्थिति (जैसे परिवार में मृत्यु या खून के रिश्ते में किसी का विवाह) के आधार पर दी जाती है।

भले ही कैदी पैरोल के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है, सक्षम प्राधिकारी इसे अस्वीकार कर सकता है यदि, उसकी राय में, कैदी की रिहाई समाज के हित में नहीं है या ऐसी आशंका है कि रिहाई पर कैदी फरार हो सकता है।

अक्सर मौत की सजा पाने वाले कैदी को भी पैरोल पर रिहा नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई हत्याओं के दोषी या आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराए गए कैदी भी पैरोल के लिए पात्र नहीं हैं।

'जेलें और उनमें निरुद्ध व्यक्ति' संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों ने जेल अधिनियम के तहत किसी कैदी को पैरोल पर रिहा करने के लिए अपने नियम बनाए हैं।

पैरोल राज्य कार्यकारिणी द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संबंध में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं और पैरोल देने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानवीय आधार पर लिया जाता है।

Q 59. उत्तर: D

व्याख्या :

अनुच्छेद 39 के तहत राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-

- ✓ नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है
- ✓ समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम संभव हो सके
- ✓ आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का आम नुकसान के लिए संकेन्द्रण नहीं होता है
- ✓ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो।

Q 60. उत्तर: D

व्याख्या :

अनुच्छेद 36 के अनुसार, भाग IV में 'राज्य" शब्द का वही अर्थ है जो भाग III में है। इसलिए, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल हैं। इस तरह ये न सिर्फ विधायिका के लिए बल्कि कार्यपालिका के लिए भी निर्देश हैं।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के भाग IV (भाग VI में नहीं) में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है।

Q 61. उत्तर: D

व्याख्या

कथन 1 गलत है: प्रश्नकाल के विपरीत, प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठाना सदस्यों के लिए उपलब्ध एक अनौपचारिक उपकरण है।

कथन 2 गलत है: अल्प सूचना प्रश्न वह है जो दस दिन से कम का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।

Q 62. उत्तर: C

व्याख्या :

मौलिक अधिकारों से संबंधित निर्णयों की सही समय सीमा इस प्रकार है:

- ✓ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- ✓ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- ✓ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
- ✓ ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

Q 63. उत्तर: B

व्याख्या :

इस समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है।

स्वतंत्रता के बाद के काल में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था।

मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे लेकिन 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ाकर 30 कर दी गई। सभी तीस सदस्य केवल लोकसभा से हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

Q 64. उत्तर: A

व्याख्या :

कथन 1 सही है: राज्यसभा की तरह, विधान परिषद एक सतत सदन है, अर्थात यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं होता है।

कथन 2 गलत है: इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो,हर सदस्य छह साल तक उस पद पर रहता है।

कथन 3 गलत है: रिक्त सीटें हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनावों और नामांकन (राज्यपाल द्वारा) द्वारा भरी जाती हैं। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य भी पुनः चुनाव और पुनःः नामांकन के लिए पात्र होते हैं।

Q 65. उत्तर: C

व्याख्या

अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध।—(1) मानव तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम निषिद्ध हैं और

इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। (2) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

अनुच्छेद 24ः कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध - चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

Q 66. उत्तर: C

व्याख्या :

इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक सिद्धांत है और संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है।

कुछ मौलिक अधिकारों के विपरीत, जो सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित हैं और विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं।

Q 67. उत्तर: B

व्याख्या :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार, राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है।

स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

Q 68. उत्तर: C

व्याख्या :

भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग 1753 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था।

CAG भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख है। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।

उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। यही कारण है कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि CAG भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। वह भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतीकों में से एक हैः अन्य हैं सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग।

Q 69. उत्तर:C

व्याख्या :

राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा में कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों की आवश्यकता होती है जिनमें राज्यों की रुचि होती है।

कथन 1 और 2 सही हैः संसद में कुछ प्रकार के विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा या अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक।

कथन 3 गलत हैः एक संवैधानिक संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

कथन 4 सही हैः धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही संसद में पेश किया जा सकता है

Q 70. उत्तर: A

व्याख्या :

42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग (IV A) में अनुच्छेद 51A को शामिल करके भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए।

86 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई।

44 वें और 48 वें संशोधन में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया है।

Q 71. उत्तर- D

व्याख्या :

भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित छूट प्राप्त है (अनुच्छेद 361):

- ✓ राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है।
- ✓ राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी भारतीय अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
- ✓ राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी भारतीय अदालत से जारी नहीं की जाएगी।
- ✓ भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी दीवानी मामले के लिए दो महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान नागरिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन दो महीने का नोटिस आवश्यक है।

Q 72. उत्तर: C

व्याख्या :

अनुच्छेद 51A के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा -

- ✓ संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना;
- ✓ उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया;
- ✓ भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना;
- ✓ देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना;

- ✓ धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना; महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना;
- ✓ हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना;
- ✓ जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना;
- ✓ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना;
- ✓ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना;
- ✓ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ सके;
- ✓ माता-पिता या अभिभावक जो भी, उसे छह से चौदह वर्ष की आयु के अपने बच्चे या, जैसा भी मामला हो, को शिक्षा के अवसर प्रदान करने होंगे।

Q 73. उत्तर: C

व्याख्या :

संविधान के अनुच्छेद 64 के प्रावधान के अनुसार, यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के तहत किसी भी कारण से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति इस दौरान राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार, उस अवधि के दौरान जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है या उस अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है या कार्यों का निर्वहन कर रहा होता है, उपसभापति अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करेगा।

अनुच्छेद 65(3) के अनुसार, इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ प्राप्त होंगी।

राष्ट्रपति (कार्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार, यदि उपराष्ट्रपति इस अवधि के दौरान इस्तीफा दे देता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।

Q 74. उत्तर: B

व्याख्या :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:

- ✓ वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
- ✓ वह पांच साल तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालय) का न्यायाधीश रहा हो।
- ✓ उसे दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालय) का वकील होना चाहिए।
- ✓ राष्ट्रपति की राय में उसे एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए।

Q 75. उत्तर: D

व्याख्या :

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- ✓ यह उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है।
- ✓ यह राज्य सरकारों के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है।
- ✓ यह राज्य सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाता है, यदि वे इसे आवश्यक समझते हैं। यह विशेष रूप से पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर वैवाहिक राहत जिसमें विवाह की शून्यता, न्यायिक तलाक, दांपत्य की बहाली, या विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा से संबंधित मामलों को शामिल करता है।
- ✓ यह साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों को सरल बनाता है ताकि पारिवारिक न्यायालय किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो सके।
- ✓ यह अपील के केवल एक अधिकार का प्रावधान करता है जो उच्च न्यायालय में होगा।

Q 76. उत्तर: B

व्याख्या :

कथन 1 सही है: उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

कथन 2 सही है: उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार संभालने तक पांच साल के कार्यकाल से अधिक अवधि तक पद पर रह सकता है। वह उस पद के लिए पुनः निर्वाचन हेतु भी पात्र है। वह कितनी भी बार के लिए निर्वाचित हो सकता है।

कथन 3 गलत है: उपराष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया भी जा सकता है।

Q 77. उत्तर.A

व्याख्या :

संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित हैं। संसद को इन्हें विनियमित करने का अधिकार भी है।

भारत की संसद को कानून बनाने, क्षेत्राधिकार व्यवस्थित करने और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को संशोधित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य उच्च न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है।

Q 78. उत्तर: C

व्याख्या :

जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

इसी प्रकार, वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है जब सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं।

Q 79. उत्तर: B

व्याख्या :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, भारत सरकार का कानूनी नाम 'भारत संघ' है। इस अनुच्छेद के खंड (1) के अनुसार, भारत सरकार भारत संघ के नाम पर मुकदमा कर सकती है या मुकदमा दायर कर सकती है।

Q 80. उत्तर: B

व्याख्या :

अधिकार पृच्छा

- ✓ इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट से'। यह किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है ।
- ✓ यह रिट तभी जारी किया जा सकता है जब किसी क़ानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र का वास्तविक सार्वजनिक कार्यालय शामिल हो, इसे निजी या मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता
- ✓ अन्य चार रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण) के विपरीत, इसकी मांग पीड़ित आलावा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है।

Q 81. उत्तर: A

व्याख्या :

राज्यों द्वारा लगाए गए, एकत्र किए गए और रखे गए करः

- ✓ भू-राजस्व
- ✓ कृषि आय पर कर
- ✓ कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क
- ✓ कृषि भूमि के संबंध में संपत्ति शुल्क
- ✓ भूमि और भवनों पर कर
- ✓ खनिज अधिकारों पर कर
- ✓ मानव उपभोग के लिए मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क।

Q 82. उत्तर: C

व्याख्या :

संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। जबकि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 281, 151(1) और 338(6) के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती हैं।

Q 83. उत्तर: B

व्याख्या:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया। इस भाग का शीर्षक 'पंचायतें' है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं।

इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243(G) से संबंधित है।

यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। इसने उन्हें संविधान के दायरे में ला दिया है।

Q 84. उत्तर: A

व्याख्या

जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वहः

- ✓ विधेयक पर अपनी सहमति देता है, या
- ✓ विधेयक पर अपनी सहमति को रोकता है, या
- ✓ विधेयक को (यदि यह धन विधेयक नहीं है) संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है।
- ✓ हालाँकि, यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है।

जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति यह कर सकता हैः

- ✓ विधेयक पर अपनी सहमति देता है, या
- ✓ विधेयक पर अपनी सहमति को रोकता है, या
- ✓ राज्यपाल को विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश देता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना अनिवार्य नहीं है, भले ही विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा फिर से पारित किया गया हो और उनके विचार के लिए फिर से भेजा गया हो।

Q 85. उत्तर:C

व्याख्या

जे. बी. कृपलानी ने भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद, अगस्त 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लोकसभा के पटल पर पहला अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इंदिरा गांधी को 15 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, बल्कि लोकसभा महासचिव को लिखित सूचना देनी होती है।

अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही रखा जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

Q 86. उत्तर: D

व्याख्या:

एक राज्य विधायिका व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर लगा सकती है। लेकिन, किसी भी व्यक्ति द्वारा देय ऐसे करों की कुल राशि ₹2,500 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य विधायिका बिजली की खपत या बिक्री पर कर लगा सकती है। लेकिन ऐसी बिजली की खपत या बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जो (A) केंद्र द्वारा उपभोग किया जाता है या केंद्र को बेचा जाता है; या (B) केंद्र या संबंधित रेलवे कंपनी द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपभोग किया जाता है या उसी उद्देश्य के लिए केंद्र या रेलवे कंपनी को बेचा जाता है।

Q 87. उत्तर: A

व्याख्या:

कथन 1 सही हैः विधानसभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसकी अधिकतम

सदस्य संख्या 500 और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 निर्धारित है। इसका अर्थ है कि राज्य की जनसंख्या के आकार के आधार पर इसकी सदस्य संख्या 60 से 500 तक भिन्न भिन्न होती है।

कथन 2 सही हैः परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई तय की गई है और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 तय की गई है। इसका मतलब है कि परिषद का आकार विधानसभा की सीटों की संख्या पर निर्भर करता है संबंधित राज्य. ऐसा राज्य के विधायी मामलों में सीधे निर्वाचित सदन (विधानसभा) की प्रधानता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

कथन 3 गलत हैः हालांकि संविधान ने अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय की है, एक परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या संसद द्वारा तय की जाती है।

Q 88. उत्तर: C

व्याख्या:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 149 में वर्णित हैं।

Q 89. उत्तर: D

व्याख्या:

अनुच्छेद 156(1) के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक पद पर रहेगा; अर्थात राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 156(4) के अनुसार, राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेता।

राष्ट्रपति एक राज्य में नियुक्त राज्यपाल को शेष अवधि के लिए दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।

Q 90. उत्तर: B

व्याख्या:

भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर का वरीयता क्रम इस प्रकार है -

- ✓ राष्ट्रपति,
- ✓ उपाध्यक्ष,
- ✓ प्रधान मंत्री,
- ✓ राज्यों के राज्यपाल (अपने राज्य में),
- ✓ पूर्व राष्ट्रपति एवं
- ✓ उप प्रधान मंत्री
- ✓ भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समान हैं।

Q 91. उत्तर: C

व्याख्या

संविधान (अनुच्छेद 76) में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। वह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

भारत सरकार के अन्य कानून अधिकारी में भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये महान्यायवादी को उसकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करते हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल महान्यायवादी का पद संविधान द्वारा निर्मित है । दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है।

भारत का संविधान (अनुच्छेद 148) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के एक स्वतंत्र पद का प्रावधान करता है। वह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।

Q 92. उत्तर: D

व्याख्या:

चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी और लद्दाख में केवल एक-एक लोकसभा सीट है।

त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में प्रत्येक में 2 लोकसभा सीटें हैं।

गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक दूसरे में मिला दिया गया है।

Q 93. उत्तर: B

व्याख्या:

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होने के बाद संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।

आपातकाल समाप्त होने के छह महीने की समाप्ति पर कानून निष्क्रिय हो जाते हैं।

Q 94. उत्तर: D

व्याख्या:

संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं।

उसे कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है; उसे संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर नहीं रहता, भले ही उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है।

CAG के कार्यालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं। इस प्रकार, यह संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं।

संविधान (अनुच्छेद 149) संसद को संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में CAG के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा की जाएगी।

तदनुसार, संसद ने सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। केंद्र सरकार में खातों को ऑडिट से अलग करने के लिए इस अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया था।

Q 95. उत्तर: D

व्याख्या

संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। ये संविधानेतर निकाय हैं। कार्य संचालन के नियमों के अंतर्गत इसका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय एवं परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।

यदि प्रधानमंत्री कैबिनेट समिति का सदस्य है, तो इसकी अध्यक्षता

प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य मंत्री कैबिनेट समिति का अध्यक्ष तभी होता है जब उस समिति में प्रधानमंत्री शामिल न हो।
संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति में प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसलिए इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नहीं करते हैं।

Q 96. उत्तर: B

व्याख्या:

1983 में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र-राज्य संबंधों पर तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग को सभी क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच और समीक्षा करने और उचित बदलाव और उपायों की सिफारिश करने का उत्तरदायित्व दिया गया था।
महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे उल्लिखित हैं:

- ✓ अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर-राज्य परिषद जिसे अंतर-सरकारी परिषद कहा जाता है, स्थापित की जानी चाहिए।
- ✓ अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का उपयोग बहुत संयमित ढंग से किया जाना चाहिए, चरम मामलों में अंतिम उपाय के रूप में जब सभी उपलब्ध विकल्प विफल हो जाते हैं।
- ✓ अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए और ऐसी कुछ और सेवाएँ बनाई जानी चाहिए।

Q 97. उत्तर: A

व्याख्या:

कोई भी विधेयक जो राजस्व या व्यय से संबंधित है, एक वित्त विधेयक होता है। धन विधेयक भी एक विशिष्ट प्रकार का वित्त विधेयक है, जिसमें केवल अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट मामले होते हैं।
सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं।
संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल सामान्य विधेयकों या वित्तीय विधेयकों के लिए है, न कि धन विधेयकों या संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए।
धन विधेयक के मामले में, लोकसभा के पास अधिभावी शक्तियाँ होती हैं, जबकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिए।
यदि विधेयक लोकसभा के विघटन के कारण पहले ही समाप्त हो चुका है, तो कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा ऐसी बैठक बुलाने के इरादे को अधिसूचित करने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है तो संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है (क्योंकि इस मामले में विधेयक समाप्त नहीं होता है)।

Q 98. उत्तर: C

व्याख्या:

जब लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है और सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है।
अध्यक्ष की तरह, जब उपाध्यक्ष भी अध्यक्षता कर रहा होता है, तो वह पहली बार में मतदान नहीं कर सकता है, वह केवल मत के बराबर होने की स्थिति में ही मतदान कर सकता है।
इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए वह लोकसभा के विचार-विमर्श में भाग नहीं ले सकते।
जब अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे किसी भी प्रश्न पर बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार होता है।

Q 99. उत्तर: C

व्याख्या:

राज्य विधानमंडल के सदस्यों को जूरी सेवा से छूट दी गई है।

- ✓ जब राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तो वे न्यायालय में लंबित किसी मामले में साक्ष्य देने और गवाह के रूप में प्रस्तुत होने से इनकार कर सकते हैं।
- ✓ राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान और ऐसे सत्र की शुरुआत से 40 दिन पहले और समाप्ति के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- ✓ यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में ही उपलब्ध है, आपराधिक मामलों या निवारक हिरासत के मामलों में नहीं।

Q 100. उत्तर: B

व्याख्या:

पहली लोकसभा के लिए 489 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने 364 सीटें हासिल की थी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) 16 सीटें हासिल कर विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी।
पहली बार, 1969 में लोकसभा में 'विपक्ष के नेता' की मान्यता दी गई। इस प्रकार कांग्रेस (O) के राम सुभग सिंह को चुना गया। किसी पार्टी के नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए, उस पार्टी के पास लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या का 10 प्रतिशत (जिसे मावलंकर नियम भी कहा जाता है) होना चाहिए।

Q 101. उत्तर: D

व्याख्या:

केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर या बाहर उधार ले सकती है या गारंटी दे सकती है, लेकिन दोनों संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर।
हालाँकि कोई राज्य भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता; एक राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर उधार ले सकती है या गारंटी दे सकती है।
अभी तक संसद द्वारा केंद्र की उधार सीमा तय करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।

Q 102. उत्तर: C

व्याख्या:

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
उसे राज्यसभा में किसी भी प्रस्ताव पर वोट करने की शक्ति नहीं है।
वह राज्यसभा में बहस में भाग ले सकता/सकती है, लेकिन किसी प्रस्ताव पर मत बराबरी की स्थिति में ही अपना वोट दे सकता/सकती है।
जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में किसी बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता/सकती सकती है।
हालाँकि, वह ऐसे समय में भी सदन में उपस्थित होकर बोल सकता है और बिना वोटिंग के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।

Q 103. उत्तर: B

व्याख्या:

अनुच्छेद 94 (c) के अनुसार, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक इसके लिए कि कम से 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी जाए।

Q 104. उत्तर: D

व्याख्या:

शून्यकाल भारतीय संसदीय द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है। इस शब्द का प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं है।

शून्यकाल की अवधारणा मूल रूप से भारतीय संसद के पहले दशक में शुरू हुई जब सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने की आवश्यकता महसूस हुई।

संसद के शुरुआती दिनों में दोपहर 1 बजे भोजनावकाश होती थी। इसलिए, सांसदों के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का अवसर दोपहर 12 बजे उपलब्ध हो गया और इसकी अवधि दोपहर के भोजन के लिए सदन स्थगित होने तक एक घंटे का निर्धारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप उस घंटे को प्रचलित रूप से शून्यकाल के रूप में जाना जाने लगा और इस दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को शून्यकाल के मुद्दों के रूप में जाना जाने लगा। समय के साथ दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा शून्यकाल के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए जाते रहे हैं।

नियम पुस्तिका का हिस्सा न होने के बावजूद इसे नागरिकों, मीडिया, सांसदों और पीठासीन अधिकारियों से मिलने वाले समर्थन से इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है।

Q 105. उत्तर: B

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है या आसन्न होती है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं।

आपातकाल की उद्घोषणा को उद्घोषणा जारी होने के एक महीने के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत (सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम दो-तिहाई बहुमत) से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।

संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक उसे निचले सदन का विश्वास प्राप्त है। अर्थात लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

Q 106. उत्तर: C

व्याख्या:

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित तीन प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है।

- ✓ संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम।

लेकिन एक अपवाद है। यदि कोई शहरी क्षेत्र है जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो राज्यपाल उस क्षेत्र को औद्योगिक टाउनशिप के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है।

नगर पालिका के सभी सदस्यों का चुनाव सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।

Q 107. उत्तर: D

व्याख्या:

स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट (1947) में मंत्रियों का संविभाग इस प्रकार थाः

- ✓ जगजीवन राम- श्रम
- ✓ डॉ. राजेंद्र प्रसाद-खाद्य एवं कृषि
- ✓ कूवरजी होर्मूसजी भाभा-वाणिज्य
- ✓ सरदार बलदेव सिंह-रक्षा

पुनर्गठित अंतरिम सरकार (1946) में प्रमुख मंत्रियों का संविभाग इस प्रकार थाः

- ✓ जगजीवन राम- श्रम
- ✓ डॉ. राजेंद्र प्रसाद- खाद्य एवं कृषि
- ✓ कूवरजी होर्मुसजी भाभा- खदान और इलेक्ट्रिकल वर्क्स
- ✓ सरदार बलदेव सिंह- रक्षा

Q 108. उत्तर: C

व्याख्या:

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं।

संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 के आयरिश संविधान से अपनाया था। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से कॉपी किया गया था।

Q 109. उत्तर: B

व्याख्या:

यह एक पूर्णतः मनोनीत निकाय है, अर्थात् अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

औद्योगीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे शहर के प्रशासन तथा एक ऐसा शहर जो अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन अन्य प्रकार से राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की जाती है।

एक छावनी बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित किया जाता है, जबकि एक अधिसूचित क्षेत्र समिति राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित की जाती है।

Q 110. उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार, ऐसी स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय का सत्र बुलाने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थायी न्यायाधीश नहीं हों, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

Q 111. उत्तर: D

व्याख्या:

उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है।

महाभियोग के आरोपों को आरंभिक सदन (प्रस्ताव लाने वाले सदन) में विशेष बहुमत के बजाय प्रभावी बहुमत द्वारा समर्थित होना अनिवार्य है।

भारत के राष्ट्रपति के विपरीत, जिस पर 'संविधान के उल्लंघन' के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

Q 112. उत्तर: D

व्याख्या:

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से मूल सूची में चार नए निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया:

- ✓ अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना।
- ✓ अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा करना और इसे बेहतर बनाना तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना।
- ✓ अनुच्छेद 39: बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
- ✓ अनुच्छेद 39A: समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

Q 113. उत्तर: D

व्याख्या:

केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर सुनवाई करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत,निम्नलिखित स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होगा-

- ✓ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या
- ✓ एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच, और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच, या
- ✓ दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में, यदि कोई प्रश्न (विधि या तथ्य का) शामिल है, जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है, तो अन्य अदालतों को इससे बाहर रखा जाएगा;

Q 114. उत्तर: A

व्याख्या:

समाजवादी सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। वे राज्य को निम्नलिखित के लिए निर्देशित करते हैं:

- ✓ लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना (अनुच्छेद 47)।
- ✓ समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना (अनुच्छेद 39A)।
- ✓ अनुच्छेद 47 के तहत, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और ड्रग्स के सेवन पर प्रतिबंध लगाना गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है।

Q 115. उत्तर: A

व्याख्या:

हालाँकि निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-वादयोग्य हैं, तथापि किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। निदेशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-वादयोग्य हैं, अर्थात, इनके उल्लंघन की स्थिति में न्यायालयों द्वारा इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

Q 116. उत्तर: C

व्याख्या:

राज्यसभा में सीटों की स्थिति इस प्रकार है:

- ✓ कर्नाटक: 12
- ✓ गुजरात: 11
- ✓ ओडिशा: 10
- ✓ केरल: 9

Q 117. उत्तर: A

व्याख्या:

अधिकार पृच्छा एक न्यायिक आदेश है जो सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति से यह बताने के लिए कहता है कि वह (पुरुष/स्त्री) किस अधिकार से उक्त पद पर आसीन है। यदि यह पाया जाता है कि पद धारक का उक्त पद से संबंधित कोई वैध अधिकार नहीं है, तो उसे पद छोड़ने के लिए यह रिट जारी किया जाता है।

रिट उस व्यक्ति को सार्वजनिक पद से बेदखल करने के लिए जारी किया जाता है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है।

तदनुसार, इस रिट का उपयोग किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, यह नागरिकों को सार्वजनिक पद के वंचन से बचाता है, जिस पर उनका अधिकार हो सकता है।

अधिकार पृच्छा रिट के लिए याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है, भले ही वह पीड़ित व्यक्ति न हो। यह लोकस-स्टैंडि के पारंपरिक नियम के विपरीत है,जिसके अनुसार, केवल वह व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, केवल वही निवारण हेतु न्यायालय का रुख कर सकता है।

Q 118. उत्तर: C

व्याख्या:

विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुसार, सरकारों को किसी की संपत्ति, स्वतंत्रता या जीवन से वंचित करने की स्थिति में न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। सरकारों को ऐसे कानून भी बनाने चाहिए जो तर्कसंगत, साम्यिक और न्यायपूर्ण हों।

यदि कोई कानून विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण या अनुचित हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा पलटा जा सकता है।

भारतीय संविधान में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं होने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ‟विधि की सम्यक प्रक्रिया‟ एक बुनियादी अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, सरकार को किसी के जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति को छीनने की अनुमति नहीं है।

विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिकी संविधान की देन है, परंतु इसे भारतीय परिवेश के अनुसार संशोधित किया गया है। भारत में, विधि की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार नागरिकों को मनमानी विधायी और मनमानी कार्यकारी कार्रवाई दोनों से संरक्षण प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जिस कानून को अतार्किक, अन्यायपूर्ण या अनुचित मानता है, उसे पलटा जा सकता है।

Q 119. उत्तर: D

व्याख्या:

हालांकि निदेशक सिद्धांत न तो कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और न ही कानूनी निवारण प्रदान करते हैं, तथापि ये निम्नलिखित तरीकों से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं:

- ✓ वे सरकार के प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं। जनता इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जांच कर सकती है।
- ✓ ये न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाशस्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। इन सिद्धांतों ने न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के प्रयोग में मदद की है, जो किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने की शक्ति है।
- ✓ ये सिद्धांत एक आम राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं। 'एक सत्तारूढ़ दल को, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, इन सिद्धांतों को स्वीकारना होता है।

Q 120. उत्तर: D

व्याख्या:

प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना।

एक तारांकित प्रश्न (तारा द्वारा चिन्हित) के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है।

अतारांकित प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं आता।

Q 121. उत्तर: C

व्याख्या:

सरकारिया आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसकी घनिष्ठ राजनीतिक संबद्धता न हो या जिसने हाल के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो।

भारत सरकार ने 9 जून, 1983 को न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता (अन्य सदस्य - बी. शिवरामन और डॉ. एस.आर. सेन) में सरकारिया आयोग का गठन किया था।

Q 122. उत्तर: D

व्याख्या:

जब दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बनाने का अनुरोध करती हैं, तो संसद उस मामले को विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है। इस प्रकार बनाया गया कानून केवल उन राज्यों पर लागू होता है जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे कानून को केवल संसद द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, संबंधित राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नहीं। उपरोक्त प्रावधान के तहत प्रस्ताव पारित करने का प्रभाव यह होता है कि संसद उस मामले के संबंध में कानून बनाने की हकदार हो जाती है जिसके लिए उसके पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। उपरोक्त प्रावधान के तहत पारित कानूनों के कुछ उदाहरण पुरस्कार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 1955 हैं; वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972; जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974; शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976; और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994।

Q 123. उत्तर: D

व्याख्या:

संसद में बजट निम्नलिखित चरणों से गुजरता है।

- ✓ बजट की प्रस्तुति
- ✓ आम चर्चा
- ✓ विभागीय समितियों द्वारा जांच
- ✓ अनुदान की मांगों पर मतदान
- ✓ विनियोग विधेयक का पारित होना
- ✓ वित्त विधेयक का पारित होना

Q 124. उत्तर: C

व्याख्या:

2011 के 97वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसके लिए राज्य से सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है (अनुच्छेद 43B)।

Q 125. उत्तर: A

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, लोक अदालत के लाभ इस प्रकार हैं:

- ✓ कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत की मूल विशेषताएं प्रक्रियात्मक लचीलापन और विवादों की त्वरित सुनवाई हैं। लोक अदालत द्वारा दावे का आकलन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्त अनुप्रयोग नहीं होता है।
- ✓ विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे बातचीत कर सकते हैं जो नियमित अदालतों में संभव नहीं है।
- ✓ लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे सिविल कोर्ट के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा यह गैर-अपील योग्य होता है, जिससे अंततः विवादों के निपटारे में देरी नहीं होती है।

Q 126. उत्तर: D

व्याख्या:

अनुच्छेद 48 (A) के तहत, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा और देश के जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करना संविधान में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक है। साथ ही, यह अनुच्छेद 51(A) के तहत उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक है।

Q 127. उत्तर: C

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

लेकिन किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी।

Q 128. उत्तर: D

व्याख्या:

संविधान स्पष्ट रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची पर संघ सूची की प्रधानता और राज्य सूची पर समवर्ती सूची की प्रधानता सुनिश्चित करता है। जहां समवर्ती सूची और राज्य सूची के बीच विरोधाभास हो, वहां समवर्ती सूची ही प्रभावी होनी चाहिए।

अवशिष्ट विषयों (अर्थात वे मामले जो तीन सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं) के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। कानून की इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट कर लगाने की शक्ति भी शामिल है।

Q 129. उत्तर: D

व्याख्या:

स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व में संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, पेशेवर कर, जल कर, जानवरों पर कर, प्रकाश कर, तीर्थयात्री कर, बाजार कर, नए पुलों पर टोल, चुंगी आदि शामिल हैं।

उपयोगकर्ता शुल्क (यानी, सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए भुगतान) में जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, सीवरेज शुल्क आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, नगर निकाय पुस्तकालय उपकर, शिक्षा उपकर, भिक्षावृत्ति उपकर आदि जैसे विभिन्न उपकर लगाते हैं।

Q 130. उत्तर: C

व्याख्या:

सही सुमेलन इस प्रकार है –

- ✓ राज्यों में विधानमंडल का गठन - अनुच्छेद 168
- ✓ विधानसभा के उपाध्यक्ष - अनुच्छेद 178
- ✓ सदस्यों के वेतन एवं भत्ते - अनुच्छेद 195
- ✓ 'धन विधेयक' की परिभाषा' - अनुच्छेद 199

Q 131. उत्तर: D

व्याख्या:

ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय है।

ग्राम न्यायालय को आपराधिक और सिविल न्यायालयों दोनों की शक्तियां प्राप्त हैं।

ग्राम न्यायालय की सीट मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होगी, वे गांवों में जाएंगे, वहां काम करेंगे और मामलों का निपटारा करेंगे।

ग्राम न्यायालय पक्षों के बीच सुलह कराकर यथासंभव विवादों को निपटाने का प्रयास करेगा।

Q 132. उत्तर. A

व्याख्या:

केंद्र सरकार ने 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसकी स्थापना एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी और इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।

यह एक उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है जो अपीलों पर विचार करता है और उसके पास प्रस्तुत शिकायतों की जांच करता है।

यह केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के दायरे में आने वाली एजेंसियों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और अन्य के बारे में अपील और शिकायतों पर विचार करता है।

Q 133. उत्तर: A

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 179 के खंड (a) के अनुसार, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई सदस्य विधान सभा का सदस्य नहीं रहने पर अपना पद रिक्त कर देगा।

अनुच्छेद 179 के दूसरे प्रावधान के अनुसार, जब भी विधानसभा भंग होती है, अध्यक्ष विघटन के बाद पुनः निर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा।

Q 134. उत्तर: C

व्याख्या:

किसी राज्य का राज्यपाल उस मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, राहत दे सकता है, राहत दे सकता है या सजा को निलंबित, कम और कम कर सकता है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

राज्यपाल मौत की सजा माफ नहीं कर सकते. भले ही राज्य के कानून में मौत की सजा का प्रावधान हो, माफी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं।

लेकिन राज्यपाल मौत की सजा को निलंबित कर सकता है, कम कर सकता है या बदल कर सकता है।

केवल राष्ट्रपति ही केंद्रीय कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उस पर विराम लगा सकता है, राहत दे सकता है, माफ कर सकता है, निलंबित कर सकता है।

वह कोर्ट-मार्शल (सैन्य अदालत) द्वारा सजा या दंड के संबंध में क्षमा, राहत, मोहलत, निलंबन, छूट या दंड को बदल भी सकता है।

Q 135. उत्तर: D

व्याख्या:

संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

- ✓ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है।
- ✓ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष पैरवी करने या कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी का पक्ष लेने की आशा में किसी का पक्ष नहीं लेंगे।
- ✓ सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिये किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। इस प्रकार, इसके कार्यों और निर्णयों की किसी के द्वारा आलोचना या विरोध नहीं किया जा सकता है। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में उसके अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए निहित है।
- ✓ संसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र की गारंटी दी है। हालांकि, संसद इसे बढ़ा सकती है।

Q 136. उत्तर: B

व्याख्या:

जब कोई आरोपी व्यक्ति न्यायिक हिरासत में होता है, तो उसे हिरासत में रखा जाता है और संबंधित मजिस्ट्रेट की निगरानी में रखा जाता है। इसके विपरीत, जब कोई आरोपी व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है, तो वह शारीरिक रूप से पुलिस के नियंत्रण में होता है और उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है।

मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बिना न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान संदिग्ध (आरोपी) से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है। फिर भी, यदि अदालत उसके सामने लाए गए तथ्यों के आधार पर आवश्यक समझती है तो वह संबंधित अधिकारी को आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे सकती है।

Q 137. उत्तर: C

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा रिट जारी कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है जबकि एक उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति या सरकार या प्राधिकरण के खिलाफ रिट जारी कर सकता है या अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर केवल तभी रिट जारी कर सकता है, जब कार्रवाई का कारण हो। इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होता है।

अनुच्छेद 32 के तहत एक उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 226 के तहत एक उपाय विवेकाधीन है और इसलिए, एक उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है।

Q 138. उत्तर: B

व्याख्या:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत, राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति में, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियां अपने हाथ में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है।

राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है।

इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकता है, हालाँकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है।

Q 139. उत्तर: B

व्याख्या:

प्राक्कलन समिति लोकसभा की एक समिति है। समिति में लोकसभा के 30 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होंगे, जिन्हें एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से प्रचारात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार हर साल सदन द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाएगा।

अध्यक्ष को अपने सदस्यों में से समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है।

Q 140. उत्तर: A

व्याख्या:

संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकते हैं। इस सूची में आपराधिक कानून और प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, वन, वजन और माप जैसे विषय हैं।

संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। इस सूची में रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतर-राज्य व्यापार और वाणिज्य, जनगणना और लेखा परीक्षा जैसे विषय हैं।

राज्य विधानमंडल के पास 'सामान्य परिस्थितियों में' राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ हैं। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, थिएटर और जुआ जैसे विषय हैं।

Q 141. उत्तर: B

व्याख्या:

सातवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1956: राज्यों के चार श्रेणियों यानी भाग A, भाग B, भाग C और भाग D में मौजूदा वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया।

- ✓ उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया।
- ✓ दो या दो से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान।
- ✓ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

Q 142. उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय संविधान में राज्य मंत्रियों की कानूनी जवाबदेही प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रावधान है कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या, इसकी जांच किसी भी अदालत में नहीं की जाएगी। अतः न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता।

संविधान के अनुच्छेद 164 की तरह, राज्य की मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति जवाबदेह बनाया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 के तहत, एक मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पर पद धारण करता है और उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है।

Q 143. उत्तर: A

व्याख्या:

संसद 'अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून' बना सकती है। इस प्रकार, संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर भी लागू होते हैं।

राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होता है।

Q 144. उत्तर: D

व्याख्या:

एक तारांकित प्रश्न (तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है) के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न आ सकते हैं।

दूसरी ओर, अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

Q 145. उत्तर : D

व्याख्या:

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधान के बजाय कानून द्वारा स्थापित एक इकाई है।

इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा पारित कानून यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के परिणामस्वरूप की गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं।

इसका अध्यक्ष भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए और सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) जिसके पास मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, शामिल होने चाहिए।

Q 146. उत्तर: A

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है।

महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। उन्हें कई कार्यकालों के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

संविधान महान्यायवादी को क्षमादान देने का अधिकार नहीं देता है। क्षमादान की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं।

Q 147. उत्तर: D

व्याख्या:

अनुच्छेद 317 के अनुसार, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति के ऐसे आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने में संसद की भूमिका होती है, और उन्हें अनुच्छेद 124 में दिए गए तरीके से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है।

Q 148. उत्तर: D

व्याख्या:

संविधान के अनुच्छेद 280(2) के अनुसार, संसद कानून द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं और उनके चयन के तरीके को निर्धारित कर सकती है।

इसके अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हताएं, वेतन और शक्तियां आदि को परिभाषित किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Q 149. उत्तर: D

व्याख्या:

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझता है।

2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित कर दिया। हालाँकि, 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन और एनजेएसी अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया।

परिणामस्वरूप, पहले वाली कॉलेजियम प्रणाली फिर से क्रियाशील हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला चतुर्थ न्यायाधीश मामले (2015) में सुनाया। न्यायालय ने कहा कि नई प्रणाली (यानी NJAC) न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी।

Q 150. उत्तर: A

व्याख्या:

1988 में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में संसद की सलाहकार समिति की एक उप-समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का सुझाव दिया। इसने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

- ✓ गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के साथ पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली।
- ✓ जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इसे जिले में योजना एवं विकास एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- ✓ तीनों स्तरों पर सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए।
- ✓ जिला कलेक्टर को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए।